RNI No. : TNHIN/2013/52520 ■ वर्ष - 13 ■ अंक - 291 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » बुधवार » 20-05-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 'वोट चोरी' का हॉरर शो जनता के बीच टायं-टायं फिस्स : नकवी

6 भोजशाला: इतिहास के आइने में सत्य की खोज

7 भारत में एटर्स को अपने ही लोग बुरी तरह ट्रोल करते हैं : अमीषा पटेल

फर्स्ट टेक

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पेंशन वितरण 25 मई से शुरू होगा : सतीशन

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने मंगलवार को कहा कि इस महीने की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्ड पेंशन का वितरण 25 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सतीशन ने यह भी कहा कि इस उद्देश्य के लिए 1,070 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केरल सरकार 62 लाख पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह प्रदान करती है। पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में यह पेंशन राशि 1,600 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी गई थी। पिछली सरकार ने अप्रैल 2026 तक के सभी पेंशन भुगतानों को मंजूरी दे दी थी।

रूस ने बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण का अभ्यास किया

मॉस्को/एपी। रूस ने मंगलवार को अपनी परमाणु शक्तियों की व्यापक आजमाइश शुरू की, जिसमें परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण का अभ्यास भी शामिल है। यह कवायद तब शुरू की गई, जब यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमलों में तेजी आई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिवसीय अभ्यास में 64,000 सैनिक, 200 से अधिक मिसाइल प्रक्षेपण यंत्र, 140 से अधिक विमान, 73 युद्धपोत और 13 पनडुब्बियां शामिल होंगी, जिनमें से आठ परमाणु-युक्त अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन सैन्य अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य हमले के खतरे की स्थिति में तैयारियों को पूरा रखना होगा।

ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस रेलगाड़ी पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं

देहरादून/भाषा। ऋषिकेश के योगनगरी रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रैक बदलते समय उज्जैनी एक्सप्रेस रेलगाड़ी पटरी से उतर गयी जिससे उसकी तीन बोगियां क्षतिग्रस्त हो गयीं । अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी । सोमवार रात करीब 9:40 बजे योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास हुई इस घटना के समय वाहन में कोई यात्री सवार नहीं था। यह ट्रेन इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर और योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार दुर्घटना में स्टेशन पर लगी लोहे की रेलिंग भी टूट गई । पटरी से उतरते समय रेलगाड़ी में इतनी जोर से झटका लगा कि आसपास के लोगों को धमाके जैसी आवाज सुनाई दी । घटना के चार घंटे पहले रेलगाड़ी इंदौर से 1050 यात्री लेकर ऋषिकेश पहुंची थी।

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

फैक मिडिया

सबसे घातक सोशल मिडिया,
जो बढ़ा रहा अपराध रोज।
कुछ भी कर दे अपराध कोई ,
कर नहीं पा रहे उसे खोज।
हो रहे भ्रमित पढ़ फेक न्यूज़,
कर रहे धूर्त सब गिद्ध भोज।
वैमनस्य घृणा आतंक द्वेष,
फैलाने वाले करे मौज।।

उच्चतम न्यायालय ने दिया फैसला

रेबीज संक्रमित व खतरनाक आवारा कुत्तों को 'जान से मारने' की दी अनुमति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या खतरनाक आवारा कुत्तों को ''जान से मारने'' (यूथेनेशिया) की अनुमति दे दी और कहा कि सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में कुत्तों से नुकसान या हमले के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने का अधिकार भी शामिल है। अपनी तरह के पहले आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब मनुष्यों की सुरक्षा और जीवन की तुलना जानवरों के हितों और कल्याण के मुकाबले की जाती है, तो संवैधानिक संतुलन स्पष्ट रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के पक्ष में होना चाहिए।

जब मनुष्यों की सुरक्षा और जीवन की तुलना जानवरों के हितों और कल्याण के मुकाबले की जाती है, तो संवैधानिक संतुलन स्पष्ट रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के पक्ष में होना चाहिए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगहों पर भेजने व उनके बंध्याकरण संबंधी अपने सात नवंबर, 2025 के निर्देशों को वापस लेने के अनुरोध वाली सभी याचिकाओं और आवेदनों को खारिज कर दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार सर्वोपरि है। अदालत ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई हो और जहां बार-बार कुत्तों के काटने या आक्रामक हमलों से जनसुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा हो, वहां स्थानीय अधिकारी कुत्तों को ''जान से मारने'' का निर्णय ले सकते हैं।

कारीगर और बुनकर राष्ट्र की जीवंत विरासत का बेहतरीन उदाहरण : राष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को पूर्वोत्तर के बुनकरों एवं कारीगरों को देश की जीवंत विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हुये उनसे आग्रह किया कि वे इस अमूल्य परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये कारीगर और बुनकर वही थे जिन्होंने 26 जनवरी को आयोजित 'एट होम' स्वागत समारोह के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने तथा निमंत्रण किट तैयार करने में योगदान दिया था।

बयान में कहा गया है, ''उदाहरण के लिए, नागालैंड के कारीगरों ने केले के रेशे और बांस का उपयोग करके टोकरियां बनाईं, असम के बुनकरों ने शॉल बनाए। मणिपुर के कारीगरों ने काली मिट्टी के बर्तन बनाए और सिक्किम के कारीगरों ने प्राकृतिक रेशों का उपयोग करके उत्पाद तैयार किए।''

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के साथ इस संवाद के दौरान, कारीगरों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' रिसेप्शन के लिए काम करने के अपने अनुभव साझा किए और अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वे (कारीगर एवं बुनकर) राष्ट्र की जीवंत विरासत का बेहतरीन उदाहरण हैं और उनसे आग्रह किया कि वे इन अमूल्य परंपराओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं।

असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कारीगरों और बुनकरों से परस्पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है।

मुर्मू ने कारीगरों और बुनकरों को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनका कलात्मक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

ट्रंप के हाथ में है मोदी का 'रिमोट कंट्रोल' : राहुल गांधी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायबरेली (उप्र)/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को दावा किया कि मोदी का 'रिमोट कंट्रोल' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है।

रायबरेली और अमेठी के अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए कहा कि मोदी देश के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने को कहते हैं जबकि लोगों को नौकरी और खाना तक भी नहीं मिल पा रहा है।

रायबरेली से कांग्रेस सांसद

गांधी ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या सपने देख रहे हैं और देशवासियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं। लोगों को घर पर खाना बनाने के लिए रसोई गैस भी नहीं मिल पा रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक कारें खरीदो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यह आदमी किस दुनिया में जी रहा है।''

रायबरेली ज़िले के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के खिरोन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान राहुल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ''खैर, उनका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है।'' उन्होंने कहा, ''आपने डोनाल्ड ट्रंप का भाषण जरूर सुना होगा। वह कहते हैं कि मैं दो मिनट में उनका (मोदी का) राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। इस बीच, एपस्टीन फाइल्स बंद ही रहती हैं। नरेन्द्र मोदी 24 घंटे विदेश दौरे पर रहते हैं। वह कभी खुद को अमेरिका से बचाने की कोशिश करते हैं तो कभी नॉर्वे का दौरा करते हैं। वह हाथ जोड़कर कहते हैं, 'कृपया मुझे माफ कर दो, एपस्टीन फाइल मत खोलो, अदाणी जी के खिलाफ एक मामला है, उसे बंद कर दो।''

जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत : शिवराज

भुवनेश्वर/भाषा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से उर्वरक खरीदने में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया तथा राज्यों और किसानों से जैविक खेती को एक विकल्प के तौर पर तेजी से अपनाने की अपील की। भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए, चौहान ने कहा कि केंद्र वैश्विक आपूर्ति की दिक्कतों के बावजूद किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, ''मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक आसानी से नहीं मिलते। भारत सरकार हमारे किसानों के लिए जहां भी उपलब्ध हैं, वहां से उर्वरकों को खरीदने की पूरी कोशिश कर रही है।''

ईरान पर हमले के बारे में एक घंटे बाद ही फैसला लेने वाला था : ट्रंप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान पर फिर से हमले शुरू करने का फैसला लेने से महज एक घंटे दूर थे, लेकिन कतर और यूएई सहित मध्यस्थों से यह संदेश मिलने के बाद कि शांति वार्ता में तेहरान 'उचित रवैया' अपना रहा है, उन्होंने यह कदम फिलहाल टाल दिया।

ट्रंप ने 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में पत्रकारों से कहा, ''मैं एक घंटे बाद निर्णय लेने ही वाला था और हम तैयार थे... अभी हमले हो रहे होते।'' ट्रंप यहां 'व्हाइट हाउस' के 'ईस्ट विंग' में बन रहे 'बॉलरूम' के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे।

ट्रंप ने कहा, शायद आज हम किसी खूबसूरत 'बॉलरूम' की बात नहीं कर रहे होते। हम उस (हमलों के) बारे में बात कर रहे होते। हम उसी स्थिति में थे, जहां मैंने फैसला कर लिया था। तभी उनका फोन आया। उन्हें पता चल गया था कि मैंने फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा, ''सर, क्या आप हमें कुछ और दिन दे सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे उचित रवैया अपना रहे हैं।''

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वार्ताकारों ने बताया कि पिछले दो दिनों में ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रगति हुई है।

ट्रंप ने कहा, पिछले दो दिनों में उन्होंने फोन करके बताया कि उन्होंने काफी प्रगति की है, क्योंकि हम उन्हें अपने साथ बातचीत में शामिल किए हुए हैं। मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, कुछ हद तक बहरीन और कुछ अन्य देश इसमें शामिल हैं। हम उनसे बातचीत करा रहे हैं। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। यह एक टीम की तरह है।''

चाहे वह यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम शांति प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ओस्लो/भाषा। भारत और नॉर्डिक देशों ने मंगलवार को अपने संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा, स्थिरता, नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नॉर्डिक देशों के समकक्षों के साथ वार्ता की।

ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश

नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, ''चाहे वह यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्षों के शीघ्र समाधान और शांति प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे।''

अन्य नॉर्डिक नेताओं ने भी नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के मोदी के आह्वान का समर्थन किया।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा, ''हमने अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया, एक नियम-आधारित व्यवस्था और यूक्रेन में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की आवश्यकता पर जोर दिया और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजने का प्रयास किया।''

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने कहा कि नॉर्डिक देशों के भारत के साथ कई साझा उद्देश्य हैं, जिनमें नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रन फ्रॉस्टडॉटिर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की मौजदगी में कहा, ''लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुपक्षवाद के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें स्वाभाविक साझेदार बनाती है।'

मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देशों का ''आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट और एकजुट रुख है : कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं।''

रुपया 50 पैसे टूटकर 96.70 प्रति डॉलर के नए निचले स्तर पर

मुंबई/भाषा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया मंगलवार को 50 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार के अंत में 96.70 प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति के बीच मजबूत डॉलर और विदेशी पूंजी की बाजार से निकासी के कारण रुपए पर दबाव रहा। रुपया 2026 में एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। पिछले आठ सत्रों में डॉलर के मुकाबले रुपए में 2.48 रुपए या 2.64 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह सात मई को 94.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से रुपए की स्थिति अब भी 'नाजुक' बनी हुई है।

सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन पर भारत और वियतनाम कर रहे विचार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और वियतनाम ने मंगलवार को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। दोनों देशों ने अपनी विस्तारित व्यापक सामरिक साझेदारी के अनुरूप संयुक्त रूप से सैन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान जियांग के बीच हुई बैठक का मुख्य एजेंडा रक्षा संबंधों का विस्तार था। यह बैठक हनोई में हुई।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।''

सूत्रों ने बताया कि सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग सिंह-जियांग बैठक के प्रमुख बिंदुओं में से एक था। यह भी पता चला है कि वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

सिंह सोमवार को दो-दिवसीय दौरे पर वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वार्ता के बाद, भारत और वियतनाम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री का हनोई दौरा भारत और वियतनाम के अपने संबंधों को उन्नत व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के कुछ दिनों बाद हुआ।

मंत्रालय ने सिंह-जियांग की मुलाकात के बारे में कहा, दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।''

ग्रेटर नोएडा दहेज मौत मामला:

पोस्टमार्टम में महिला के कई आंतरिक अंगों के फटने का पता चला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नोएडा/भाषा। ग्रेटर नोएडा में कथित दहेज हत्या मामले में जान गंवाने वाली 24 वर्षीय महिला के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का पता चला है, जिनमें मस्तिष्क में रक्तस्राव, आंतरिक अंगों का फटना शामिल है। इसके अलावा महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान शामिल हैं।

महिला के 'विसरा' के नमूने फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका के बाएं नथुने और मुंह से खून बह रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्तिष्क के बीच में और बाईं ओर हेमाटोमा (बड़ी रक्त वाहिकाओं से रक्त रिसाव) हुआ।

'पीटीआई-भाषा' को हासिल हुई रिपोर्ट में कहा गया कि लीवर, तिल्ली और दाहिना गुर्दा फट गया था।

रिपोर्ट में बांह और जांघ पर चोट के निशान के बारे में भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी विषैले पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है।

इससे पहले मंगलवार को ईकोटेक-3 थाने की पुलिस ने कहा था कि मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है और चिकित्सकों ने कोई अंतिम राय नहीं दी है।

नागर की मौत रविवार रात को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जलपुरा गांव में स्थित उसकी ससुराल के तीन मंजिला मकान की छत से कथित रूप से गिरने के बाद हुई थी।

हालांकि महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसकी ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या की और यह न तो आत्महत्या थी और न ही दुर्घटना।

पुलिस ने नागर के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्राथमिकी में नामजद अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे: क्रेमलिन

मॉस्को/भाषा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के सहायक ने यह जानकारी दी। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत सितंबर में समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सरकारी समाचार एजेंसी 'तास' ने अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए राष्ट्रपति कार्यालय 'क्रेमलिन' के सहायक यूरी उशाकोव के हवाले से अपनी खबर में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक की योजना बनाई गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। इस महीने की शुरुआत में, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य देशों के दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया था।

दिल्ली के परिवहन नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार बनाने पर कर रहे हैं काम : गडकरी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार नए एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड गलियारे के निर्माण के जरिये दिल्ली के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक एवं भविष्य के लिए तैयार करने पर काम कर रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनएच-148 एनए के डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुस्ता रोड जंक्शन तक छह लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग का निरीक्षण करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि संपर्क में सुधार के लिए सरकार के प्रयास ईंधन की खपत को कम करने, प्रदूषण को घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में मदद करेंगे। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में विश्वस्तरीय, हरित, सतत एवं निर्बाध परिवहन नेटवर्क स्थापित होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान में दिल्ली में 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली की आगामी परियोजनाओं में 34,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि भीड़भाड़, प्रदूषण एवं ईंधन खपत कम की जा सके। 2015 में मोदी सरकार ने दिल्ली को जाम से मुक्त करने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, '' प्रधानमंत्री की सरकार के सत्ता में आने पर हमने दिल्ली को जाम से मुक्त करने की योजना बनाई थी जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना एवं आवागमन को सुगम बनाना है।''

सरकार ने ओएनजीसी को परिचालन संबंधी संकट में डाला : कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के गैस एवं तेल क्षेत्र में 'वाटर इंजेक्शन' में कमी किए जाने के कारण इस सरकारी कंपनी के सामने परिचालन संबंधी संकट खड़ा हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने यह दावा भी किया कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण ही 'गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम' (जीएसपीसी) भी मुश्किल में है। गोहिल के आरोपों पर फिलहाल इन कंपनियों या पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''घरेलू पेट्रोल, डीजल, गैस का 70 प्रतिशत उत्पादन ओएनजीसी करती है। इसमें भी ओएनजीसी के तीन तेल एवं गैस फील्ड-मुंबई हाई, नीलम और हीरा फील्ड 59 प्रतिशत तेल एवं गैस का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन तीनों में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक 'वॉटर इंजेक्शन' कम कर दिया गया। इसके कारण 2014 में एक साल में 369.5 करोड़ मीट्रिक टन का नुकसान देश को हुआ।'' उन्होंने दावा किया कि इस कारण आज ओएनजीसी परिचालन संबंधी संकट का सामना कर रही है।

उत्तराखंड के विकास में खंडूरी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा: नितिन नवीन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

खंडूरी (91) का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को देहरादून के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। खंडूरी की बेटी और उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि उनके पिता ने पूर्वाह्न करीब 11 बजे अंतिम सांस ली।

नवीन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद खंडूरी के निधन की खबर बेहद दुखद है।''

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि खंडूरी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और सुशासन के सर्वोच्च आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''उत्तराखंड के विकास की यात्रा में उनके योगदान और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के रूप में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा।'' उन्होंने कहा, ''मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।'' भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने खंडूरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि यह उत्तराखंड और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। बलूनी ने कहा कि खंडूरी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन, ईमानदार राजनीति और उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित कर दिया। गढ़वाल से सांसद बलूनी ने कहा, ''अपनी सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक आदर्श स्थापित किया। उत्तराखंड राज्य के गठन और विकास में उनका योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा।''

भाजपा नेता ने कहा, ''मैं भगवान बद्रीविशाल से प्रार्थना करता हूं कि वह उस महान आत्मा को अपने दिव्य चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार और समर्थकों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।''

शांति अधिनियम चुनौती याचिका को न्यायालय ने बेहद संवेदनशील विधायी नीतिगत मुद्दा बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में देयता की सीमा 3,000 करोड़ रुपए निर्धारित करने वाले 2025 के कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि यह ''एक बेहद संवेदनशील विधायी नीतिगत मुद्दा'' है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने पाया कि भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं विकास (शांति) अधिनियम, 2025 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए मुद्दे ''आर्थिक नीति'' से संबंधित हैं। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ''हमारी चिंता यह है कि यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है और किसी व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचती है, तो क्या हमारे पास इसके लिए एक मजबूत मुआवजा तंत्र मौजूद है?'' अदालत में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कुल दायित्व की सीमा तय करने सहित तीन मुख्य मुद्दे हैं। भूषण ने 2011 में जापान में हुई फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना का हवाला देते हुए दलील दी, ''यदि कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो उससे होने वाला नुकसान इससे सैकड़ों गुना अधिक होता है।'' उन्होंने दलील दी कि सरकार नीति के माध्यम से जो चाहे कर सकती है लेकिन वह नागरिकों के अधिकारों की बलि नहीं चढ़ा सकती। पीठ ने कहा, ''यह एक अत्यंत संवेदनशील विधायी नीतिगत मुद्दा है।'' पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि प्रौद्योगिकी बाहर से ही लानी होगी और आश्चर्य व्यक्त किया कि यदि दायित्व की सीमा तय नहीं की गई तो यहां संचालन करने कौन आएगा। न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के होने पर सरकार भी मुआवजा देगी। पीठ ने टिप्पणी की कि दायित्व पर सीमा लगाने से किसी भी घटना के पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। भूषण ने दलील दी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की लागत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की लागत से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, ''मैं अदालत से सरकार की किसी नीति में हस्तक्षेप करने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन वह नीति नागरिकों की सुरक्षा की तिलांजिल नहीं दे सकती।'' उन्होंने दावा किया कि अधिनियम के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं। पीठ ने कहा, ''आप हमें एक भी ऐसा देश बताइए, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली का उत्पादन नहीं करता हो।'' भूषण ने कहा कि जापान और जर्मनी जैसे देशों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन करना बंद कर दिया है और वहां देयता पर कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में यह सीमा 1.54 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत में निर्धारित सीमा से 100 गुना अधिक है। भूषण ने दावा किया कि यह अधिनियम विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षा मानकों में ढिलाई बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय करते हुए कहा, ''आपकी कुछ आशंकाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। हम उन आशंकाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।''

ट्रांसपोर्टरों की मांगों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री से चर्चा, जल्द समाधान की उम्मीद : गडकरी

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली-एनसीआर में 21 मई से ट्रांसपोर्टर हड़ताल की घोषणा के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से चर्चा की है और इसका जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है। ट्रांसपोर्टर संगठन एआईएमटीसी ने दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों पर बढ़ाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिभार (ईसीसी) और बीएस-4 या उससे पुराने वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के विरोध में तीन दिन के लिए हड़ताल पर जाने की घोषणा की है।

अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के 68 से अधिक ट्रांसपोर्ट संगठन तीन दिन तक अपने परिचालन बंद रखेंगे। यह निकाय देशभर में 95 लाख ट्रक चालकों और 26 लाख निजी बस, टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है।

गडकरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस हड़ताल के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''मैंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से चर्चा की है। हम जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे।'' एआईएमटीसी ने इस हड़ताल के आह्वान के लिए केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और दिल्ली सरकार की 'अन्यायपूर्ण और मनमानी' नीतियों को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने वाणिज्यिक वाहनों पर ईसीसी में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ हर साल पांच प्रतिशत शुल्क वृद्धि का भी निर्णय लिया था।

नीट पेपर लीक मामले में आरोपी कोचिंग सेंटर मालिकों की इमारतें ध्वस्त करना चाहिए: शिरसाट

छत्रपति संभाजीनगर/भाषा। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने मंगलवार को कहा कि नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के स्वामित्व वाली इमारतों को ध्वस्त कर देना चाहिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने लातूर में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) संचालित करने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पत्रकारों से बातचीत में शिरसाट ने नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों की संपत्तियों और बड़े-बड़े विज्ञापनों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ''बड़े से बड़ा नेता भी इतने विज्ञापन नहीं करवा सकता। लेकिन अगर हम किसी छोटे से गांव में जाएं, तो वहां कोचिंग क्लास के विज्ञापन मिल जाएंगे। यह पैसा छात्रों की फीस से आता है। इसलिए, नीट मामले में सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करना काफी नहीं है। इन लोगों की संपत्ति की जांच और उसे जब्त किया जाना चाहिए।'' मंत्री ने आगे कहा, ''गिरफ्तार किए गए इन लोगों के मालिकाना हक वाली इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।'' विपक्षी दलों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का आंतरिक मामला है।

केंद्र अपनी विफलताओं के लिए प. एशिया संघर्ष को जिम्मेदार ठहराएगा: ईंधन के दाम में वृद्धि पर मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि अब वह अपनी सभी ''विफलताओं'' के लिए पश्चिम एशिया संघर्ष को जिम्मेदार ठहराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति लोगों से छिपाते हुए देश को ''अघोषित लॉकडाउन'' की ओर ले जा रही है।

ईंधन की कीमतों में एक और बढ़ोतरी के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मान ने कहा, ''वे इसे कई गुना बढ़ा देंगे। असल में, (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी अब हर चीज के लिए युद्ध को दोषी ठहराएंगे। वह कहेंगे कि युद्ध हो रहा है।'' संगरूर के सतोज गांव में भूमिगत बिजली तारों की प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत करने के बाद मुख्यमंत्री संवाददाताओं से बात कर रहे थे। केंद्र सरकार को देश की जनता को ईंधन और एलपीजी के भंडार की जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। मान ने कहा, ''कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद, अब वे देश को बचाने की बात करने लगे हैं। लेकिन चुनाव से पहले देश की स्थिति अच्छी थी।'' उन्होंने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के लिए विफल आर्थिक और विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ''धीरे-धीरे वे हर चीज पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। वे कार मालिकों से वाहन का इस्तेमाल नहीं करने को कह रहे हैं, लोगों से दफ्तर न जाने और घर से काम करने, सोना नहीं खरीदने, समारोह आयोजित नहीं करने को कह रहे हैं।''

खर्च कम करने के लिए महाराष्ट्र को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनायें टालनी चाहिए : रोहित पवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को खर्च कम करने और महंगाई से नागरिकों को संरक्षण देने के लिए शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को टाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए पवार ने कहा कि इन परियोजनाओं को एक साल के लिए धीमा करने से राज्य का खर्च कम होगा।

उन्होंने कहा, ''आज शक्तिपीठ मार्ग की जरूरत नहीं है। इस पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय, सरकार मेट्रो रेल के काम और बुलेट ट्रेन परियोजना को एक साल के लिए धीमा करके खर्च कम कर सकती है।'' उन्होंने कहा कि अगर सरकार खर्च कम करना चाहती है, तो उसे इस तरह के बड़े खर्च कम करने चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि आम लोगों को बचत के उपायों से परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों को राज्य को चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए। पवार ने कहा कि एनसीपी (एसपी) प्रमुख, शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा था कि अगर देश मुश्किलों का सामना कर रहा है तो मिलकर काम करें। किसानों के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि कई किसान पुराने बकाया के कारण बैंकों से नया ऋण नहीं ले पा रहे हैं।

खंडित मूर्तियों के लिए संग्रह केंद्र खोलेगी दिल्ली सरकार : रेखा गुप्ता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक विसर्जन और 'रीसाइक्लिंग' के लिए समर्पित संग्रह केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश आस्था का सम्मान बनाए रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है।

गुप्ता ने कहा, वर्षों तक जिन मूर्तियों को लोग अपने घरों में भगवान के रूप में पूजते हैं, खंडित हो जाने के बाद अक्सर उन्हें पीपल के पेड़ों के नीचे, नदी किनारे, पार्कों या सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे समर्पित संग्रह केंद्र स्थापित करेगी, जहां नागरिक अपनी खंडित मूर्तियों को सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे और बाद में इन मूर्तियों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से 'रीसाइकल' कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा प्रयास है कि आस्था का सम्मान भी बना रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यह पहल केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी का आंदोलन बनेगी।

गुप्ता ने इस मुहिम को पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सीधे दिल्लीवासियों से सुझाव मांगे हैं ताकि जनभागीदारी से इस योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी आस्था का सम्मान और दिल्ली की सफाई, दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं। उनके मुताबिक, दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है।

प्रधान ने नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, त्रुटिरहित परीक्षा आयोजित करने पर जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके ''सुरक्षित, सुचारू और त्रुटिरहित'' आयोजन का निर्देश दिया। यह जानकारी अधिकरियों ने दी।

अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी खामियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षा के आयोजन में पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

अधिकारियों के अनुसार, ''मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नीट-यूजी पुनर्परीक्षा सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ''सुरक्षित, सुचारू और त्रुटिरहित'' तरीके से आयोजित की जानी चाहिए।''

मंत्री ने अधिकारियों को सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि परीक्षा व्यवस्थाओं की सख्त निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

प्रधान ने परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता न करने और छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अनियमितताओं के आरोपों के बीच तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। प्रधान ने इससे पहले घोषणा की थी कि नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी अनियमितताओं को देखते हुए अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी।

नाले के पास छोड़ी गई डेढ़ महीने की बच्ची बचाई गई, पिता गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली में एक व्यक्ति ने डेढ़ महीने की अपनी बच्ची को रोहिणी इलाके में एक नाले के पास कथित रूप से छोड़ दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि शिकायत मिलने के तीन घंटे के अंदर ही बच्ची को बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी सज्जन कुमार (20) बच्ची के जन्म से खुश नहीं था और उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद कुमार को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, 17 मई को बुध विहार थाने में एक नवजात बच्ची के अपहरण की सूचना मिली। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने तड़के उसकी बेटी को अगवा कर लिया और आरोप लगाया कि वह बेटी के जन्म से नाखुश था। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।

ईपीएफओ सदस्यों को जल्द मिलेगी यूपीआई से पैसा निकालने की सुविधा, परीक्षण पूरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारक जल्द ही यूपीआई के जरिये कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकाल कर सीधे अपने बैंक खातों में अंतरित कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान गेटवे के जरिये कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पैसा निकालने के लिए परीक्षण का काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि ईपीएफओ सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। मांडविया ने कहा, ''हमने यूपीआई भुगतान गेटवे का उपयोग करके ईपीएफ से पैसा निकालने की सुविधा देने को लेकर परीक्षण कार्य पूरा कर लिया है। इस सुविधा के तहत निकाली गई राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी।'' श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जिसके तहत ईपीएफ के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी और एक बड़ा हिस्सा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके उनके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा। सदस्य अपने लिंक किए गए बैंक खातों में पैसा अंतरित करने के लिए उपलब्ध पात्र ईपीएफ राशि देख सकेंगे।

वे अपने बैंक खातों में सुरक्षित रूप से धन अंतरण सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन पूरा करने को लिंक किए गए यूपीआई पिन का उपयोग कर सकेंगे। एक बार बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित हो जाने के बाद, सदस्य एटीएम से निकासी समेत अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। इससे सात करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ होगा। वर्तमान में, ईपीएफओ सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते तक पहुंचने के लिए निकासी दावों के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। स्वचालित निपटान प्रणाली के तहत, निकासी दावों का निपटान आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से तीन दिन के भीतर बिना किसी 'मैन्युअल' हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो जाता है। स्वचालित निपटान प्रणाली की सीमा को मौजूदा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में ईपीएफओ सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए तीन दिन के भीतर अपने ईपीएफ से पैसे प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने सदस्यों तक पहुंच बढ़ाने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए व्हॉट्सएप का उपयोग करने की पहल की है। इस सुविधा के तहत, सदस्य ईपीएफओ के पंजीकृत व्हॉट्सएप नंबर पर 'हेलो' लिखकर संदेश भेज सकते हैं। सुरक्षा और आश्वासन के लिए इस नंबर पर हरे रंग का निशान लगा होता है। वे ईपीएफओ से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी संदेश प्राप्त कर सकते हैं।

अन्नाद्रमुक के दोनों गुट अपने रुख पर अडिग, पलानीस्वामी ने आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग नहीं मानी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ईके पलानीस्वामी ने मंगलवार को पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की, लेकिन उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला बागी गुट झुकने को तैयार नहीं हुआ।

एक दिन पहले ही पलानीस्वामी ने बागियों को विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे आने और बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था। पलानीस्वामी ने पार्टी मुख्यालय में करीबी नेताओं के साथ लगभग दो घंटे लंबी बैठक की, लेकिन उन्होंने आम परिषद बुलाने की बागियों की मांग को स्वीकार नहीं किया। वरिष्ठ नेताओं सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले बागी गुट के किसी भी सदस्य ने पलानीस्वामी से हाथ मिलाने के निमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। पलानीस्वामी की ओर से आयोजित बैठक से बाहर निकलने के बाद वरिष्ठ नेता ओएस मनियन ने कहा कि रचनात्मक चर्चा हुई, लेकिन आम परिषद बुलाने के बारे में कोई विचार नहीं हुआ। पलानीस्वामी के करीबी नेता बीवी रमण ने बताया कि लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में करीब 80 जिला सचिव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पलानीस्वामी के साथ मजबूती से खड़े हैं और पार्टी आने वाले दिनों में जीत हासिल करने की रणनीति बनाएगी। रमण ने संवाददाताओं से कहा, ''बैठक में 80 से अधिक जिला सचिवों ने हिस्सा लिया। कुछ सचिव समय पर पार्टी मुख्यालय नहीं पहुंच पाने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।'' मणियन ने कहा कि बैठक में विजयभास्कर के उस दावे पर चर्चा नहीं हुई, जिसमें उन्होंने चुनाव में मिली हार पर चर्चा करने और ''उचित निर्णय'' लेने के लिए आम परिषद की बैठक बुलाने के संबंध में 1,000 पार्टी सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त करने की बात कही थी। इस बीच, षणमुगम ने संवाददाताओं से बात करते हुए पलानीस्वामी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक ओर पलानीस्वामी असंतुष्ट नेताओं को बातचीत के लिए बुला रहे हैं, दूसरी ओर वह 31 जिला सचिवों को उनके पदों से हटा रहे हैं। षणमुगम, वेलुमणि और विजयभास्कर उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें पार्टी के विभिन्न पदों से हटा दिया गया है। षणमुगम ने कहा कि वह और उनके समर्थक बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी राय जाहिर करने पर उन्हें देशद्रोही करार दिया जाना स्वीकार्य नहीं है। यह बैठक तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार को समर्थन देने वाले बागी गुट की आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। एक अन्य वरिष्ठ नेता वीवी राजन चेल्लप्पा ने कहा कि अन्नाद्रमुक ने पलानीस्वामी के नेतृत्व में अटूट समर्पण के साथ एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। चेल्लप्पा ने पोस्ट में कहा, ''हम अपने महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करने के वास्ते पूरा समर्थन और सहयोग देने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे।''

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नौ न्यायिक अधिकारियों, 10 अधिवक्ताओं के नामों की मंजूरी

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नौ न्यायिक अधिकारियों और 10 अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 18 मई को हुई बैठक में नियुक्ति के लिए इन नामों को मंजूरी दी। जिन न्यायिक अधिकारियों के नामों को मंजूरी दी गई है, उनमें डॉ. पी मुरुगन, एमडी सुमति, एस अल्ली, सी थिरुमगल चंद्रशेखर, धर्मलिंगम लिंगेश्वरन, कार्तिकेयन बालथंडायुथम, षणमुगम कार्तिकेयन, बलुचामी मुरुगेसन और एन गुणशेखरन शामिल हैं।

वहीं, जिन अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी गई है उनमें नटराजन रमेश, जीके मुथुकुमार, रामकृष्णन राजेश विवेकानंदन, शंकरनारायणन रविकुमार, नागराजन दिलीप कुमार, एलप्पन मनोहरन, कृष्णास्वामी गोविंदराजन, रजनीश पथियिल, के. अप्पादुरई और रामासामी अनिता शामिल हैं। एक अन्य निर्णय में, कॉलेजियम ने मुंबई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबलकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी, अद्वैत महेंद्र सेठना और प्रवीण शेषराव पाटिल के नामों को मंजूरी दी।

तमिलनाडु : भारी बारिश के कारण बिजली का तार घर पर गिरने से अथूर में तीन लोगों की मौत

डिंडीगुल/भाषा। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एक घर पर बिजली का तार गिरने से एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और कॉलेज के एक छात्र सहित तीन लोगों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान करुपैया (41), उनकी पत्नी सुधा (37) और 18 वर्षीय पड़ोसी सुब्रमण्यशिव के रूप में हुई, जो उनकी मदद के लिए दौड़े थे। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण अथूर के अग्रहारा स्ट्रीट स्थित करुपैया के घर की ऊपरी मंजिल पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। पड़ोसियों ने बिजली बोर्ड को सूचना दी, जिसने बिजली आपूर्ति रोक दी। वे तीनों पीड़ितों को अथूर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेम्पाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवासियों ने अस्पताल के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए डिंडीगुल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है।

पुडुचेरी विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष ने थट्टनचावडी विधानसभा सीट से रंगासामी का इस्तीफा स्वीकार किया

पुडुचेरी/भाषा। पुडुचेरी विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष ए. अनबलगन ने मंगलवार को एआईएनआरसी नेता और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी का थट्टनचावडी विधानसभा सीट से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। रंगासामी ने नौ अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों में थट्टनचावडी और मंगलम सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा सचिव जे. दयालाने द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने मंगलम सीट बरकरार रखी है। अस्थायी अध्यक्ष ने थट्टनचावडी से रंगासामी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रंगासामी ने 13 मई को वरिष्ठ भाजपा नेता ए. नमस्सिवयम और एआईएनआरसी विधायक मल्लाडी कृष्णा राव के साथ पांचवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा में एआईएनआरसी की संख्या अब घटकर 11 रह गई है और पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की कुल संख्या 17 है। इसके सहयोगी दलों में भाजपा ने चार सीटें जीती हैं; अन्नाद्रमुक और एलजेके को एक-एक सदस्य मिला है।

छात्र जीवन से ही राजनीतिक सोच वाले थे सतीशन : दोस्तों और परिवार ने कहा

कोच्चि/भाषा। केरल के नए मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के कॉलेज के दिनों के दोस्त और परिवार के सदस्यों का कहना है कि वह छात्र जीवन से ही तेज राजनीतिक समझ रखने वाले नेता रहे हैं। सतीशन के 43 वर्ष पुराने मित्र और यहां के सेक्रेड हार्ट कॉलेज, थेवरा के पूर्व छात्र रंजीत थम्पी ने कॉलेज यूनियन चुनाव का एक दिलचस्प किस्सा याद करते हुए कहा कि सतीशन की राजनीतिक सूझबूझ उस समय भी साफ दिखाई देती थी।

थम्पी ने बताया कि उस समय कांग्रेस की छात्र इकाई केएसयू के नेता सतीशन एक बेहतरीन वक्ता और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी थे। कॉलेज चुनाव में केएसयू के सामने एसएफआई का एक बेहद लोकप्रिय उम्मीदवार था, जो अपने गायन कौशल के कारण छात्रों में काफी चर्चित था। उन्होंने कहा कि सतीशन ने ही सुझाव दिया था कि केएसयू के उम्मीदवार को भी गाना गाने के लिए तैयार किया जाए ताकि लोकप्रिय प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला किया जा सके। थम्पी ने हंसते हुए कहा, हम लोग मेरे घर के बरामदे में बैठकर केएसयू उम्मीदवार को मलयालम गीत 'नी मधु पकरू' गाने का अभ्यास कराते थे। उन्होंने बताया कि बाद में सतीशन ने इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बना दिया। थम्पी ने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, जब उम्मीदवार प्रचार के लिए कक्षाओं में जाता था, तो सतीशन पहले ही कुछ केएसयू समर्थकों को वहां बैठा देते थे, जो छात्रों के बीच से यह सवाल उठाते थे कि क्या हमारा उम्मीदवार भी प्रतिद्वंद्वी की तरह गा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद उम्मीदवार हर कक्षा में वही गीत गाता था और छात्रों से तुरंत जुड़ाव बना लेता था। अंततः वह चुनाव जीत गया।

अंबुमणि ने तमिलनाडु सरकार से ईडी मामले में बालाजी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया

चेन्नई/भाषा। पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) नेता अंबुमणि रामदास ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता सेंथिल बालाजी के खिलाफ धनशोधन मामले में न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया। पीएमके नेता ने एक बयान में कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु सरकार से पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ दायर उस मामले की जांच शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित परिवहन निगमों में नौकरी दिलाने के बहाने भोले-भाले युवाओं से करोड़ों रुपए धोखाधड़ी से एकत्र किए गए और अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए थे।

उन्होंने इस कदम को लोक प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा, चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने द्रमुक से जुड़े वर्तमान विधायक सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2011 से 2015 के बीच परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य परिवहन निगमों में चालकों, खलासियों, तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों के रूप में रोजगार के अवसर दिलाने का वादा करके हजारों व्यक्तियों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की।

मैं जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करता हूं: स्टालिन के दामाद सबरिसन

चेन्नई/भाषा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम. के. स्टालिन के दामाद एवं हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाने वाली परामर्श फर्म के संस्थापक सबरिसन वेदमूर्ति ने कहा कि वह जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। सामाजिक-राजनीतिक शोध संगठन 'पॉपुलस एम्पावरमेंट नेटवर्क' (पीईएन) के संस्थापक वेदमूर्ति ने कहा कि वह कड़ी मेहनत जारी रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम को किसी एक कारण से जोड़कर देखना सच्चाई को नहीं दर्शाता और संकेत दिया कि चुनावी रणनीति तय करने में जितनी भी उनकी भूमिका रही, उसकी जिम्मेदारी लेने से वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। टीम पीईएन की कड़ी मेहनत और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं, लेकिन चुनावी नतीजों में जो भी मेरी भूमिका रही, उसे स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं जिम्मेदारी, विनम्रता और जनता की उम्मीदों की गहरी समझ के साथ आगे बढ़ता रहूंगा।''

तमिलनाडु : अम्मा कैंटीनों के उन्नयन के फैसले का दिनाकरन ने किया स्वागत

चेन्नई/भाषा। अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने तमिलनाडु में संचालित अम्मा कैंटीनों के उन्नयन संबंधी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के निर्देश का मंगलवार को स्वागत किया और राज्य सरकार से इस योजना का और विस्तार करने की मांग की। दिनाकरन ने एक बयान में कहा, मैं मुख्यमंत्री के उस निर्देश का स्वागत करता हूं, जिसके तहत चेन्नई निगम सहित राज्यभर की 600 से अधिक अम्मा कैंटीनों में बुनियादी ढांचे में सुधार, जरूरी रसोई उपकरणों की तत्काल खरीद और जनता को गुणवत्तापूर्ण भोजन निर्बाध तरीके से उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता द्वारा शुरू की गई रियायती दर वाली सरकारी भोजनालय योजना 'अम्मा कैंटीन' को भूख के खिलाफ 'जीवनरेखा' बताते हुए कहा कि इससे छात्र, श्रमिक और अन्य जरूरतमंद लोगों को लाभ मिला है। दिनाकरन ने आरोप लगाया, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के उद्देश्य के बावजूद द्रमुक शासन के पांच वर्षों के दौरान अम्मा कैंटीनों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी, उपकरणों का अभाव और राजनीतिक कारणों से कैंटीनों को बंद किए जाने जैसी समस्याओं ने इस पहल के उद्देश्य को कमजोर किया।

एएमएमके नेता ने कहा, ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री ने अम्मा कैंटीनों के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके उन्नयन का आदेश दिया है, मैं इस फैसले का दिल से स्वागत करता हूं और तमिलनाडु के सभी पंचायत क्षेत्रों में अम्मा कैंटीन शुरू करने की मांग करता हूं, ताकि राज्य के गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं, के विरुद्ध शिकायतों का निवारण

रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस)

- रिज़र्व बैंक ने अपनी सभी विनियमित संस्थाओं को उनके ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने हेतु अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसे विनियमित संस्थाओं का आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र माना जाता है।
- रिज़र्व बैंक ने, रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबी-आईओएस) के माध्यम से अपनी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमियों से संबंधित ग्राहक शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और नि:शुल्क वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है।
- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शिकायत निवारण तंत्र के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में माना जाता है।
- किसी भी विनियमित संस्था के विरुद्ध सभी शिकायतों के लिए आरबी-आईओएस "एक राष्ट्र एक ओम्बड्समैन" दृष्टिकोण अपनाता है। अत: शिकायतकर्ता के लिए अब यह जानना आवश्यक नहीं है कि उसे किस ओम्बड्समैन योजना/कार्यालय के तहत ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
- आरबी-आईओएस के अंतर्गत नहीं आने वाली विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) द्वारा किया जाता है।
- आरबी-आईओएस और सीईपीसी के दायरे में आने वाली संस्थाओं की सूची https://cms.rbi.org.in पर देखी जा सकती है।

अगर आपको शिकायत हो तो क्या करें?

आप विनियमित संस्थाओं के विरूद्ध उसकी शाखा में या शिकायत निवारण पोर्टल पर ऑनलाइन या उसकी वेबसाइट पर बताए गए किसी अन्य तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की पावती प्राप्त करें या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।

आरबीआई ओम्बड्समैन से संपर्क कब करें?

आप निम्नलिखित मामलों में आरबीआई ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं :

- **विनियमित संस्थाओं से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर -** विनियमित संस्थाओं को की गई आपकी शिकायत की तारीख से एक वर्ष और 30 दिन के भीतर कभी भी।
- **विनियमित संस्थाओं से प्राप्त उत्तर असंतोषजनक है -** संबंधित विनियमित संस्थाओं से उत्तर प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर कभी भी।

ध्यान दें:

- आरबी-आईओएस में निर्दिष्ट शिकायत फार्म के अनुसार सभी अपेक्षित विवरण/जानकारी शिकायत में शामिल होनी चाहिए।
- शिकायत किसी अन्य मंच (जैसे न्यायालय) में निपटाई गई /लंबित नहीं होनी चाहिए या आरबीआई ओम्बड्समैन द्वारा पहले निपटाई नहीं गई हो।
- **विनियमित संस्था से संपर्क किए बिना आरबीआई ओम्बड्समैन के पास सीधे शिकायत दर्ज कराने पर उसे अस्वीकार किया जा सकता है।**

आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज करें?

विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध कोई भी शिकायत निम्न किसी भी माध्यम द्वारा दर्ज की जा सकती है:

- आरबीआई के शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल https://cms.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन।
- आरबी-आईओएस के अनुबंध में निर्दिष्ट फॉर्म में भौतिक शिकायत (पत्र / डाक) "केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर -17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ - 160017" को प्रेषित की जा सकती है।

आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें?

अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई संपर्क केंद्र के टोल-फ्री नंबर 14448 पर संपर्क कर सकते हैं।
इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) युक्त संपर्क केंद्र 24x7 उपलब्ध है, जबकि संपर्क केंद्र कर्मियों से अंग्रेजी, हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) में बात करने की सुविधा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शनिवार सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए

कृपया देखें :
भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Faqs.aspx?did=56
या
सीएमएस पोर्टल-https://cms.rbi.org.in

सर्वे

राजस्थान के बीकानेर जिले में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई। सरकारी कर्मचारियों ने घर-घर जाकर सर्वे अभियान चलाया।

भीषण गर्मी के बीच जोधपुर में गहराया जल संकट, इंदिरा गांधी नहर में पानी पहुंचने में देरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच जोधपुर जिला जल संकट का सामना कर रहा है और अधिकारियों का कहना है कि रखरखाव कार्य के लिए वार्षिक बंदी के बाद पंजाब के हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़े जाने में देरी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी ने बताया कि पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार नहर को 10 मई तक बंद रखा जाना था और 11 मई से हरिके बैराज से पानी छोड़ा जाना निर्धारित था।

उन्होंने कहा, हालांकि पंजाब क्षेत्र में मरम्मत और तकनीकी कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़े जाने में देरी हुई। सोलंकी ने बताया कि 14 मई से चरणबद्ध तरीके से हरिके बैराज से नहर में पानी छोड़ा गया। विभाग को उम्मीद है कि यह पानी 20 मई की रात या 21 मई की सुबह तक जोधपुर के कायलाना झील और तख्त सागर जलाशयों तक पहुंच जाएगा, जो शहर के प्रमुख जल स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन दोनों जलाशयों में इतना ही पानी बचा है, जिससे नहर का पानी पहुंचने तक शहर की जरूरतें पूरी हो सकें।

पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता (शहर) राजेंद्र मेहता ने कहा कि जलाशयों तक पानी पहुंचने के बाद भी उन्हें सामान्य स्तर तक भरने में करीब दो सप्ताह का समय लगेगा। उन्होंने कहा, इसके बाद ही शहर की जलापूर्ति सामान्य हो सकेगी। इस स्थिति को देखते हुए 21 मई को एक दिन की जलापूर्ति बंद रखने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अगले दिन पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जोधपुर में पेयजल की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है।

उन्होंने कहा, पूरे शहर में भारी परेशानी है और हालात लगभग जल आपातकाल जैसे हो गए हैं। खबरें हैं कि कायलाना और तख्त सागर में केवल दो दिन का पानी बचा है। करीब 20 लाख आबादी वाला शहर गंभीर जल संकट के मुहाने पर खड़ा है, जबकि सरकार चुप है। गहलोत ने पीएचईडी की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या यह पूर्व तैयारी की कमी को नहीं दर्शाता? क्या कोई ठोस जल प्रबंधन योजना नहीं बनाई गई थी? अब जब जल संकट सामने है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

पेट्रोल-डीजल की स्थिति के बारे में सच बताए राजस्थान सरकार: अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कई जगह पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने की खबरों का उल्लेख करते हुए मंगलवार को राज्य सरकार से मांग की कि वह इस बारे में सच जनता को बताए ताकि लोग आने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। गहलोत के अनुसार उनसे मिलने आए कई आगुंतकों ने कल बताया कि जोधपुर में पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है और बहुत से पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। गहलोत के अनुसार इससे जोधपुर से जयपुर तक आते हुए तीन-चार बार पेट्रोल-डीजल भरवाना पड़ रहा है क्योंकि 1000 रुपये से अधिक का ईंधन नहीं दिया जा रहा है। गहलोत के अनुसार, रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर भी कई-कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के अनुसार सरकार कह रही है कि पेट्रोल-डीजल- एलपीजी की कोई कमी नहीं है, जबकि पेट्रोल पंप मालिकों से इसकी जानकारी लेने पर वे बता रहे हैं कि सरकार ने मौखिक आदेश देकर सीमित मात्रा में पेट्रोल-डीजल देने के लिए कहा है। गहलोत ने कहा कि इसीलिए पेट्रोल पंपों पर लम्बी लाइन लग रही है। उन्होंने एक बयान में कहा, आज मीडिया में खबरें हैं कि जोधपुर के 40 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं (पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया है)। यह संकट का समय है, इसलिए सरकार जनता के सामने असत्य बोलने एवं गुमराह करने की बजाय सच बताए जिससे जनता आने वाली परेशानी के लिए तैयार रहे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सके। कांग्रेस नेता गहलोत ने कहा कि अपुष्ट जानकारियों से अफवाह फैलती है, जिससे जनता भ्रमित होती है और उथल-पुथल की स्थिति बनती है।

आठ महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का आरोप

जयपुर। राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में आठ महीने की एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। आरोप है कि बच्ची की मां ने ही उसे जानबूझकर तेजाब पिला दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना भिवाड़ी इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि सोमवार को घटना के समय पीड़ित बच्ची के पिता मोहित काम पर गए हुए थे, इसी दौरान उसकी मां ने उसे कथित तौर पर तेजाब पिला दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोमवार शाम बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिवार वाले उसे तुरंत भिवाड़ी केसरकारी अस्पताल ले गए और वहां से वे उसे एक निजी अस्पताल ले गए। सहायक उप निरीक्षक वेद प्रकाश ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को बच्ची के बारे में जानकारी अस्पताल से मिली, जिसके बाद वे अस्पताल गए और मामले के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा, पिता ने शुरुआती तौर पर अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती तेजाब पिलाया। बच्ची 'वेंटिलेटर' पर है।

राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना

जयपुर। राजस्थान के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है और मंगलवार से तेज, धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के अधिकतर भागों में 19 से 22 मई के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली, धूल भरी सतही हवाएं चलेंगी। इसके अनुसार, राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने व अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आगामी दिनों में कहीं-कहीं ऊष्ण दिन एवं ऊष्ण रात्रि की स्थिति रहेगी। उल्लेखनीय है कि लगभग समूचा राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार सुबह तक बीते चौबीस घंटे में राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा और कहीं कहीं पर ऊष्ण रात्री दर्ज की गई। इस दौरान पिलानी व चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

केंद्र सरकार से समन्वय कर खनन से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय में पूरा करें : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है तथा प्रदेश में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। हमारी सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे में विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र से समन्वय करते हुए नियमित बैठकें आयोजित करें। जिससे खनन क्षेत्र से संबंधित कार्य तय समय में पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की गरिमामयी उपस्थिति में खान एवं कोयला विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स प्रदेश में बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में लगभग 725 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई वृत्ताकार/अर्धवृत्ताकार आग्नेय चट्टानों की संरचना है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एवं सिवाना ग्रेनाइट में रेयरअर्थ एलिमेंट एवं हेवी रेयरअर्थ एलिमेंट उपलब्ध है। साथ ही, आधुनिक तकनीकी एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इसका राष्ट्रीय महत्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं, इस संबंध में खान विभाग एवं संबंधित जिला कलक्टर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करें, जिससे काम में तेजी आ सके।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राज्य में चिन्हित एवं अन्वेषित साइट्स की जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा करें, जिससे संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त भूमि का अन्यत्र प्रयोजन के लिए आवंटन नहीं हो। उन्होंने पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ गति देने के निर्देश दिए और कहा कि जिन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है, वहां पर शीघ्र ही उत्पादन कार्य शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के लिए खान विभाग के अधिकारी नियमित बैठक कर कार्य योजना बनाएं, इससे खनन कार्य में भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा।

केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अन्वेषण, नीलामी और उत्पादन प्रक्रियाओं में गति आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल का बड़ा भण्डार उपलब्ध है। रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सोलर, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने का सामर्थ्य राजस्थान में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रो-एक्टिव अप्रोच से राजस्थान खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन, निवेश अनुकूल वातावरण तथा पारदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान खनन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय से खनन से जुड़े सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान करें, जिससे निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि हो।

बैठक में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कोल इंडिया-आरवीयूएनएल संयुक्त उपक्रम, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी, डीएमएफ फंड, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियां, खनिज ब्लॉक के शीघ्र संचालन, राज्य में संचालित विभिन्न भूवैज्ञानिक एवं खनिज अन्वेषण गतिविधियां तथा प्रदेश से संबंधित खनन मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खनन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों, केंद्र से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

राजस्थान विधान सभा के 75वें वर्ष में होंगे चार बड़े कार्यक्रम : देवनानी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा के 75वें वर्ष में चार बड़े कार्यक्रम होंगे। एक वर्ष तक चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत होने वाले समारोह ऐतिहासिक और गौरवशाली होंगे। यह उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। समारोह की विशिष्टता के अनुरूप देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रमों में संसदीय और संविधान विशेषज्ञों के विशेष सत्र होंगे। सभी समारोहों में राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आमंत्रित होंगे। देवनानी ने कहा कि यह अमृत महोत्सव लोकतंत्र के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में जोड़ने वाला ऐसा राष्ट्रीय आयोजन होगा, जिसमें अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिला, युवा ऊर्जा और जनविश्वास एक साथ दिखाई देंगे। यह आयोजन भारतीय संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली आत्मा का उत्सव होगा। स्पीकर देवनानी मंगलवार को विधान सभा में राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में राजस्थान विधान सभा के 75वें वर्ष में आयोजित किये जाने वाले समारोहों की चर्चा कर रहे थे। स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के उपाध्यक्ष टीकाराम जूली, संघ के सचिव एवं विधायक संदीप शर्मा, कार्यकारिणी समिति के सदस्य विधायक पुष्पेन्द्र सिंह, श्रीचन्द कृपलानी, श्रीमती शौभा चौहान, हरिमोहन शर्मा, हमीर सिंह भायल और देवी सिंह शेखावत सहित विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा भी मौजूद रहे।

बैठक में तय किया गया कि जुलाई माह में होने वाला प्रथम कार्यक्रम राजस्थान की पहली से सोलहवीं विधान सभा तक के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का विशाल सम्मेलन होगा, जिसमें लोकतंत्र की ऐतिहासिक यात्रा को जीवंत किया जाएगा। महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट कानूनों, सामाजिक परिवर्तनकारी निर्णयों और संसदीय परंपराओं की समीक्षा की जाएगी। समारोह में पूर्व विधान सभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठतम सदस्यों का विशेष सम्मान होगा। लोकतंत्र के सफर के अनुभव और चुनौतियों, विधायी विरासत, सदन की गरिमा और विधान सभा के डिजिटल रूपान्तरण पर भी सम्मेलन में चर्चा होगी।

प्रदेश में अगस्त तक 500 ई-बसें होंगी संचालित, सार्वजनिक परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन खपत कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में पीएम ई-बस योजना एवं राज्य स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत अगस्त 2026 तक प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 ई-बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए प्रदेश में 9 अत्याधुनिक ई-बस डिपो का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार किया जा रहा है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय मे आयोजित बैठक में ई-परिवहन सेवाओं के विस्तार और प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ ई-परिवहन विस्तार योजनाओं पर चर्चा करते हुए प्रदेश में ई-बसों एवं बसों के क्रय की प्रगति की समीक्षा की।

प्रदर्शन के दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, परिसर में मची अफ़रा-तफ़री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बाड़मेर। बाड़मेर की गिरल माइंस के स्थानीय मजदूरों का आंदोलन मंगलवार को अत्यंत उग्र रूप में तब्दील हो गया। पिछले 38 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे मजदूरों के समर्थन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले, भारी संख्या में श्रमिकों और ग्रामीणों के साथ बाड़मेर कलक्ट्रेट पहुंचे। कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान आक्रोश इस कदर बढ़ा कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अचानक एक आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। विधायक द्वारा कलक्ट्रेट के भीतर पेट्रोल छिड़कने की इस सनसनीखेज घटना से पूरे परिसर में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और समर्थकों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए विधायक को आगे कोई भी कदम उठाने से रोका और स्थिति को संभाला। इससे पहले मंगलवार सुबह गिरल गांव में एक विशाल मजदूर आंदोलन जनसभा आयोजित की गई थी। इस महापंचायत में प्रदेशभर से मजदूर, विभिन्न श्रमिक संगठन, किसान, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए।

जनसभा के बाद विधायक भाटी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में श्रमिक हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर, गगनभेदी नारेबाजी करते हुए सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ बाड़मेर कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जिला मुख्यालय का घेराव कर दिया।

खुद पर पेट्रोल छिड़कने जैसी आत्मघाती स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर बात करते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया। भाटी ने कहा:

मजदूर किसी भी प्रदेश और व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उनकी मांगों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। पिछले 38 दिनों से मजदूर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं और मैं खुद पिछले 14 दिनों से उनके समर्थन में इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठा हूँ। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई।

भाटी ने इसे सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता का प्रमाण बताते हुए कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि, हजारों मजदूर और ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं, तब भी समाधान की दिशा में प्रयास न होना राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद बाड़मेर जिला मुख्यालय पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। कलक्ट्रेट परिसर को भारी पुलिस जाब्ते के साथ छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उच्च प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और विधायक व मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की मेज पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद से ही कलक्ट्रेट के बाहर मौजूद हजारों समर्थकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जो प्रशासन के खिलाफ लगातार उग्र नारेबाजी कर रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने की बजट घोषणाओं सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय विशेष योग्यजन, अनुजा निगम एवं बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट घोषणाओं सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी ली। कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बैठक लेते हुए वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की मुख्यमंत्री बजट घोषणा, स्कैमेटिक बजट, एसएनए-स्पर्श, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि, राजकाज पर लंबित पत्रावलियाँ, लंबित विधानसभा प्रश्न, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति, भूमि आंवटन संबंधित मुद्दे सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सभी विभागों की प्रगति संतोषजनक है। लंबित प्रकरणों का प्रभावी कार्ययोजना बनाकर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठक रखने के भी निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त विशेष योग्यजन निदेशालय इकबाल खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक ललित कुमार, वित्तीय सलाहकार श्रीमती अंजू सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मरीजों को बड़े अस्पताल भेजने पर 15 अगस्त के बाद होगी कार्रवाई : सम्राट चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सारण/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को जिलों में कार्यरत सरकारी चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रवृत्ति बंद की जाए।

सारण जिले के सोनपुर में विभिन्न विभागों से संबंधित जन-शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू किए गए 'सहयोग' शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ''जिलों में कार्यरत सरकारी चिकित्सक मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में भेजने की प्रवृत्ति बंद करें। यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू होगी। यदि 15 अगस्त के बाद पंचायत और जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों से सामान्य मामलों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया तो संबंधित सरकारी चिकित्सकों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'' उन्होंने कहा कि कुछ गंभीर बीमारियों अथवा विशेष मामलों को छोड़कर (जो जांच के दायरे में होंगे) मरीजों का उपचार पंचायत और जिला स्तर के अस्पतालों में ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ''सरकार जिला स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है ताकि स्थानीय स्तर पर मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। पंचायत और जिला स्तर के अस्पतालों में नई एवं अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं इस

वर्ष 15 अगस्त से पूरी तरह कार्यशील हो जाएंगी।'' उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का भरोसा मजबूत करने का आह्वान किया। 'सहयोग' शिविरों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को राज्यभर की पंचायतों में ऐसे शिविर आयोजित किए गए हैं ताकि विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित लोगों की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार इस उद्देश्य के लिए पहले ही 'सहयोग पोर्टल' और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर '1100' शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'सहयोग पोर्टल' पर दर्ज किसी आवेदन का 30 दिनों के भीतर निस्तारण नहीं करने और आदेश जारी नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन समेत सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ''पंचायत स्तर पर 'सहयोग' शिविर आयोजित कर 30 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी वास्तविक समय में निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय भी अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी करेगा।'' मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस पहल के तहत प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर 'सहयोग' शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां जन शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

'वोट चोरी' का हॉरर शो जनता के बीच टायं-टायं फिस्स : नकवी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

प्रयागराज/भाषा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों को लेकर मंगलवार को यहां कहा कि वयोवृद्ध कांग्रेस निर्मित, निर्देशित 'वोट चोरी' का हॉरर शो जनता के बीच टायं-टायं फिस्स हो रहा है।

नकवी ने कहा, जनता ने दशकों की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत को दरकिनार कर सत्तालोलुप क्षेत्रीय पार्टियों को यह सबक सिखाया है कि देश की प्राथमिकता सांप्रदायिक छल नहीं, बल्कि समावेशी बल है। उन्होंने कहा, आगामी उप्र चुनावों में कांग्रेस-सपा गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री रह चुके नकवी ने कहा कि चुनावी चक्रवात में चारो ख़ाने चित पार्टियों की चांडाल चौकड़ी लगातार धूर्ततापूर्ण धमाल करने में जुटी है। हालांकि, देश की जनता सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने वालों की खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल कर रही है। नकवी ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनतांत्रिक जनादेश के खिलाफ दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार में लगी ये पार्टियां बार बार मुंह की खा रही हैं। इन्हें जनादेश में खोट बताने की सनक से बाहर आना होगा और आत्मचिंतन करना होगा कि जनता क्यों उनकी खुराफाती सियासत को बार बार नकार रही है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने की इसकी सनक से यह पार्टी बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में धराशाई हुई है और आगे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी धूलधूसरित होगी। उन्होंने कहा कि आज भाजपा और सहयोगी दलों का भारत की 78% आबादी और 22 राज्यों में सुशासन का ध्वज लहरा रहा है। नकवी ने कहा कि वैश्विक संकट के दौर में नरेंद्र मोदी के रूप में देश को स्थिर सरकार और सक्षम नेतृत्व मिला हुआ है जो इस संकट में संकटमोचक है। मोदी ने देश के सामने आए हर संकट के समाधान का प्रमाणित और प्रभावी परिणाम दिखाया है। कुछ लोग संकट के समाधान में जुटने के बजाय सियासी व्यवधान में डट जाते हैं।

मोदी को स्वीडन में सर्वोच्च सम्मान दिया जाना भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है : खांडू

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने को मंगलवार को हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री के असाधारण नेतृत्व को दर्शाता है। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने भारत-नॉर्वे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान और नेतृत्व के लिए सोमवार को 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को स्वीडन में 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया गया है, जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के महत्व को रेखांकित करते हुए खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कूटनीतिक और वैश्विक प्रभाव के लिहाज से यह सम्मान एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

नागरिकों, कंपनियों की मदद के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने की जरूरत: सान्याल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने मंगलवार को नियमों में पारदर्शिता को लेकर अधिनियम का प्रस्ताव रखा, ताकि सभी नियम, विनियमन और नागरिकों के लिए आवश्यक शर्तें एक अलग केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकें।

इस कदम से कारोबार और जीवन स्तर में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की बड़ी खामी यह है कि अनेक नियम व विनियमन होने के बावजूद किसी को यह नहीं पता कि कौन सा संस्करण नवीनतम है। सान्याल ने उद्योग मंडल एसोचैम के भारत व्यापार सुधार सम्मेलन में कहा कि प्रस्तावित अधिनियम में यह प्रावधान होगा कि नागरिकों और कंपनियों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी नियम व विनियमन वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने कहा, ''पारदर्शिता नियम अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है। इसमें तीन तत्व होने चाहिए जिनके लिए मैं काफी समय से प्रयासरत हूं...। लेकिन इसके लिए जन दबाव की आवश्यकता है। कृपया इसमें मेरा समर्थन करें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसे हमें करने की जरूरत है।'' इसके तहत, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सभी कानून, नियम, विनियमन, प्रपत्र और अन्य नागरिक-संबंधी आवश्यकताएं अलग से बनाये गये एक केंद्रीकृत पोर्टल और संबंधित विभाग/एजेंसी के पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हों। एक बार किसी सरकारी एजेंसी को पारदर्शिता नियम अधिनियम के अनुरूप घोषित कर दिया जाए, तो अधिकारियों को तब तक नियम लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उन्हें एजेंसी की वेबसाइट और एकीकृत पोर्टल पर स्पष्ट रूप से प्रकाशित न कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों और मानदंडों को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे अंतहीन परिपत्रों की शृंखला के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। सान्याल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक 'मास्टर' परिपत्र के माध्यम से यह आसानी से किया जा सकता है। प्रस्तावित अधिनियम में अनिवार्य होना चाहिए कि पोर्टल और वेबसाइट पर किए प्रत्येक बदलाव का स्पष्ट समय अंकित हो। इससे नागरिकों को जानने में मदद मिलेगी कि कोई नियम कब से लागू हुआ या कब हटाया गया। उन्होंने कहा, ''...किसी भी कानून की जानकारी न होना कोई सुरक्षा नहीं है...। लेकिन हर नागरिक या व्यवसाय को यह जानने का उचित अवसर मिलना चाहिए कि कानून क्या है।''

योगी की टिप्पणी पर रीजीजू ने कहा: सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी कानून का पालन करें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सड़कों पर नमाज पढ़ने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी पर मंगलवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति या नेता को तनाव पैदा नहीं करना चाहिए और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सभी को कानून का पालन करना होगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बुलाए गए राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के एक सम्मेलन के बाद रीजीजू ने संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ''मेरा कहना है कि कोई भी हो, चाहे राजनेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता, हमें तनाव पैदा नहीं करना है। हर भारतीय को एक-दूसरे के साथ सद्भाव से रहना होगा। मंत्री ने कहा, ''हम सभी को एक साथ रहना है। लेकिन सभी को कानून का पालन करना होगा।'' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर चेतावनी देते हुए सोमवार को कहा था कि धार्मिक स्थलों पर अलग-अलग पालियों में धर्म से संबंधित गतिविधियां की जानी चाहिए।

आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार सड़क जाम करके नमाज या किसी अन्य धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं देगी।

जाति देखकर हो रही हैं मुठभेड़ें, महिलाओं की सुरक्षा देने में सम्राट सरकार विफल: तेजस्वी

पटना/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार कानून-व्यवस्था संभालने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में ''जाति देखकर एनकाउंटर'' किए जा रहे हैं। यादव ने यहां अपने अपने सरकारी आवास पर प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह विभाग उनके पास होने के बावजूद अपराधियों में कानून का भय नहीं है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है और सरकार केवल दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बने अभी एक महीना ही हुआ है, लेकिन इस दौरान महिला अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है।

यादव ने कहा कि पिछले छह महीने के भीतर बिहार में दो बार मुख्यमंत्री बदले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को हटाकर ''चयनित मुख्यमंत्री'' बनाया गया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा, जब हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़ या अन्य आपराधिक घटनाएं सामने नहीं आ रही हों लेकिन सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। राजद नेता ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति महिला अपराध के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है तो उसमें संवेदनशीलता की कमी है। यादव ने महिला सशक्तीकरण के सरकारी दावों पर भी सवाल उठाए।

आईपीएल की कमाई आरामदायक स्थिति दे सकती है, लेकिन लंबे करियर के लिए समर्पण जरूरी : कोहली

बेंगलूरु/भाषा। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों से आईपीएल में मिलने वाली तात्कालिक प्रसिद्धि के आकर्षण से ऊपर उठकर लंबे समय तक खेल के प्रति समर्पित रहने और व्यापक क्रिकेट जगत का सम्मान अर्जित करने का आग्रह किया। कोहली अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल 50 ओवर के प्रारूप में खेलते हैं। उन्होंने उभरते हुए क्रिकेटरों से कहा कि वे सभी प्रारूपों में खेलने वाले खिलाड़ी बनने के लिए खुद को प्रेरित करने की कोशिश करें। कोहली ने कहा, यह जुनून की बात है। आजकल बहुत से लोग जुनून को पैसे से जोड़ते हैं। जी हां, यह एक बड़ा कारक है क्योंकि जब कोई ऐसा प्रारूप आपको प्रसिद्धि, पहचान और 20 गेंदों में 40-50 रन बनाकर मिलने वाली शोहरत देता है और आईपीएल में आज लोग जिस तरह की कमाई कर सकते हैं, तो यह आपको बहुत आरामदायक स्थिति में पहुंचा सकता है। कोहली ने टेस्ट प्रारूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद संन्यास ले लिया। उन्होंने उभरते हुए क्रिकेटरों से इस कठिन लेकिन बेहद फलदायी कदम को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, वे कह सकते हैं, 'देखो, यह (टी20 क्रिकेट) शानदार है। मुझे ज्यादा देर तक दबाव झेलने की जरूरत नहीं है। मैं बस मैदान पर उतरकर गेंद को जोर से मार सकता हूं।' या फिर वे कह सकते हैं, मैं 1520 साल खेलना चाहता हूं। मैं क्रिकेट जगत में अपने नायकों की तरह पहचान और सम्मान पाना चाहता हूं और इस अवसर को भुनाना चाहता हूं।

मोदी सरकार की परियोजना के कारण ग्रेट निकोबार 'बायोस्फीयर रिज़र्व' खतरे में : रमेश

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार की गेट निकोबार परियोजना के कारण इस द्वीप का 'बायोस्फीयर रिजर्व' (संरक्षित जैवमंडल) खतरे में है। 'बायोस्फीयर रिजर्व' पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का एक विशाल और विशेष क्षेत्र होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वहां के पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों का सतत विकास सुनिश्चित करना है। पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''हमें भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर बहुत गर्व है और यह सही भी है। लेकिन 'बायोस्फीयर रिजर्व' के यूनेस्को विश्व नेटवर्क के बारे में क्या, जो समान रूप से प्रतिष्ठित हैं? उनका उद्देश्य पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना है।''

फाल्टा पुर्नमतदान: तृणमूल कांग्रेस के 'पुष्पा' जहांगीर खान चुनाव मैदान से पीछे हटे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुर्नमतदान से पहले मंगलवार को एक नाटकीय मोड़ के तहत तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव मैदान से पीछे हटने की घोषणा कर दी। उनके इस कदम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फाल्टा में एकतरफा जीत मिलने की संभावना है।

जहां एक ओर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने खान के निर्णय से दूरी बनाते हुए इसे उनका ''निजी फैसला'' करार दिया और आरोप लगाया कि चुनाव के बाद फाल्टा में भय का माहौल है। वहीं, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि खान को कोई मतदान एजेंट नहीं मिल पाया, जिसके कारण वह चुनाव मैदान से ''भाग गए।'' खान फाल्टा में प्रचार अभियान के दौरान सबसे चर्चित चेहरों में एक थे। उन्होंने फिल्म 'पुष्पा' के मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की थी और कई बार खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया था, जो दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोपों के बाद फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दिया गया था। खान ने कहा कि उन्होंने फाल्टा के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज देने का वादा किया है, जिसके चलते वह यह निर्णय लेने को प्रेरित हुए।

खान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मैं फाल्टा का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि यह क्षेत्र शांतिपूर्ण रहे तथा इसका विकास हो।''

उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री ने फाल्टा के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है, इसीलिए मैंने इस निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान प्रक्रिया से दूर रहने का निर्णय लिया है।''

ओडिशा सतर्कता विभाग ने इंजीनियर की कई संपत्तियों का पता लगाया : 33 भूखंड, चार इमारतें शामिल

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा सतर्कता विभाग ने मंगलवार को एक सरकारी इंजीनियर की कई संपत्तियों का पता लगाया जिसमें चार बहुमंजिला इमारतें, 33 भूखंड, एक फार्महाउस और एक बाजार परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने एक शिकायत के आधार पर आज सुबह भवानीपटना में सहायक अधिशासी अभियंता (एएई), आर एंड बी (सड़क और भवन) प्रभाग, की छह स्थानों पर स्थित संपत्तियों पर छापेमारी की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान विभाग के अधिकारियों ने अब तक भवानीपटना कस्बे के पास नौ एकड़ में फैले चार बहुमंजिला भवन, एक बाजार परिसर, एक फार्महाउस और कुल 39.64 एकड़ क्षेत्र में फैले 33 भूखंडों का पता लगाया है। एक अधिकारी ने बताया कि भवानीपटना के विशेष न्यायाधीश, सतर्कता द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर छह डीएसपी, आठ निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों ने छापेमारी की कार्रवाई में भाग लिया। उन्होंने बताया कि इसी बीच, सतर्कता विभाग ने एक अन्य मामले में, एक पंचायत विस्तार अधिकारी को एक कर्मचारी से उसके बकाया और नियमित पारिश्रमिक दिलवाने के लिए 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।

भविष्य में होने वाले चुनाव में सहयोगियों के साथ गठबंधन जारी रहेगा : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि भविष्य में होने वाले चुनावों में सहयोगियों के साथ गठबंधन जारी रहेगा और इसका फॉर्मूला सीट का बंटवारा नहीं बल्कि 'चुनाव में जीत' होगा।

यहां 'अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश 2026' कार्यक्रम में, जब अखिलेश से यह पूछा गया कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वह आगामी चुनावों में एक साथ प्रचार करते नजर आएंगे, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के पास गठबंधन चलाने का व्यापक अनुभव है और उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि उसके सहयोगियों को भी इस व्यवस्था से लाभ हो। यादव ने कहा, ''हमने कई गठबंधन किए हैं। हमारे पास गठबंधन का अनुभव है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगियों के लिए लाभ सुनिश्चित किया है। हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। आज जो गठबंधन है वह आगे भी जारी रहेगा।'' उन्होंने कहा कि भविष्य में गठबंधन की चर्चा सीट के लिए सौदेबाजी के इर्द-गिर्द नहीं बल्कि चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के इर्द-गिर्द घूमेगी। उन्होंने कहा, ''गठबंधन में सीट का सवाल नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने कहा था कि मुद्दा सीट का नहीं है, मुद्दा जीत का है। यही फॉर्मूला फिर काम करेगा। सवाल सीट का नहीं होगा, सवाल जीत का होगा।'' सपा प्रमुख से जब यह पूछा गया कि 'इंडिया' गठबंधन कई राज्यों में समान गठबंधन व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जानती है कि गठबंधन को कैसे बनाए रखा जाए।

जब तक मौजूदा सरकार नहीं बदलती, महंगाई बढ़ती रहेगी : राहुल गांधी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायबरेली (उप्र)/भाषा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक मौजूदा सरकार नहीं बदलती, महंगाई बढ़ती रहेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कभी नॉर्वे का दौरा करते हैं, कभी जापान का, जबकि लोगों से विदेश यात्राओं से बचने का आग्रह करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मौजूदा सरकार नहीं बदलती, महंगाई बढ़ती रहेगी।

राहुल गांधी रायबरेली जिले के बछरावां में एक बारात घर के उद्घाटन के बाद आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम एशियाई संकट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर कब्जा कर लिया - जो एक रणनीतिक स्थान है। वहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने घोषणा की कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगा। परिणामस्वरूप, पूरी दुनिया अब तेजी से तेल, उर्वरक और डीजल की गंभीर कमी का सामना करने लगी है।''

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी देश से सोना न खरीदने, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने और विदेश यात्रा से बचने का आग्रह करते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ही वह विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। उन्होंने कहा, दुख की बात यह है कि एक भयंकर आर्थिक तूफान आ रहा है, जिसे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा तूफान हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दर्शकों से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि नुकसान किसका होगा? और उन्होंने जवाब दिया, न तो अंबानी का होगा और न ही अदाणी का। वे अपने महलों में बैठे रहेंगे, जिनकी चारों तरफ से सुरक्षा है। नुकसान भारत के किसानों, मजदूरों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और रोजगार पैदा करने वाले छोटे उद्योगों का होगा। गांधी ने कहा मैं महीनों से कहता आ रहा हूं कि एक आर्थिक तूफान आने वाला है। मैंने सरकार से तैयारी करने का आग्रह किया है, क्योंकि जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और महंगाई आसमान छूएगी। फिर भी, वे कहते हैं कि राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं है। आज भी हम उनसे कहते रहते हैं- कार्रवाई कीजिए। जनता की रक्षा कीजिए। किसानों की रक्षा कीजिए। लेकिन वे कुछ नहीं करते। कभी वह (मोदी) नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान, और फिर कहीं और। क्यों? विपक्ष के नेता ने एक बार फिर दोहराया कि एक ऐसा तूफान आ रहा है, जिसका सामना भारत ने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम दिन-ब-दिन नरेन्द्र मोदी से आग्रह करते आ रहे हैं मजदूरों और छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर भी, वह क्या करते हैं? वह नॉर्वे चले जाते हैं। और नॉर्वे में वह कहते हैं, भाई अदाणी की मदद करो, अंबानी की मदद करो। यह हो रहा है। जनता को जागरूक होना चाहिए।

सुविचार

छोटे बनकर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी चीज, बड़े होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

भारत जीतेगा, हम सब जीतेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने संबंधी जो अपील की, उसका असर धरातल पर दिखाई देने लगा है। कई राजनेताओं के अलावा न्यायाधीश, कलेक्टर और कर्मचारी भी ईवी या साइकिल से दफ्तर जा रहे हैं। जम्मू के कुछ इलाकों में तांगे चलने लगे हैं, जो कई साल पहले बंद हो गए थे। लोग बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी और साइकिल का उपयोग कर ईंधन बचाने में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक टिप्पणियां कर इस मुहिम को नाकाम करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं– 'कैसा जमाना आ गया? ... अब तो हो गया विकास! ... कार से साइकिल पर आ गए। ... देश को बैलगाड़ी के युग में पहुंचा दिया। ... आगे ईश्वर ही मालिक है।' एक कहावत है– 'हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता।' अपनी सुरक्षा के लिए दरवाज़े को बंद करना भी ज़रूरी होता है। अगर तूफ़ान आ जाए और व्यक्ति दरवाज़ा बंद कर सोचे, 'मैं घर में कैद हो गया।' क्या इससे समस्या दूर हो जाएगी? वहीं, कोई व्यक्ति दरवाज़ा बंद कर सोचे, 'मैं अब अधिक सुरक्षित हूं', तो वह तूफान का मजबूती से सामना कर सकेगा। परिस्थिति एक ही है, लेकिन अपनी सोच से व्यक्ति सुखी या दुखी होता है। आज हमें यह सोचकर आगे बढ़ना है कि इस दशक में वैश्विक महामारी और विदेश में युद्धों के बावजूद हमारा देश मजबूती से खड़ा है। हम पर इनका बहुत कम असर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कार के बजाय साइकिल चला रहा है तो वह भारत माता की सेवा कर रहा है। हमारे पास साइकिल के रूप में एक अच्छा विकल्प तो है। इसकी वजह से कितने ही लोगों का सफर जारी है। तेल महंगा हो या सस्ता, साइकिल उनका साथ नहीं छोड़ेगी।

समाज और सरकार, दोनों ने साइकिल को उतना महत्त्व नहीं दिया, जितना देना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति दफ्तर जाने के लिए साइकिल खरीद ले तो लोग यह सोचते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। पिछले चार दशकों में सड़कों पर कारों और मोटरसाइकिलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। उनके बीच साइकिल कहीं गुम-सी हो गई है। उसकी घंटी सुनकर ऐसा लगता है कि 'नक्कारखाने में तूती की आवाज' वाली कहावत साइकिल के लिए ही बनी है। अगर चार दशक पहले साइकिलों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता, बेहतर प्रयोग किए जाते तो आज हमें पेट्रोल-डीजल की कीमतों की इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ती। लोगों ने बार-बार साइकिल की उपेक्षा की, लेकिन इसने हर बार अपनी अहमियत साबित की। जो लोग जरा-सी चुनौती आते ही अपनी परेशानियां गिनाते हुए मैदान छोड़कर भागने का मंसूबा बना लेते हैं, वे भारत की शक्ति और सामर्थ्य से अनजान हैं। हमारे देश ने पूर्व में भीषण अकाल, खाद्यान्न संकट, युद्धों और अंतरराष्ट्रीय दबावों का सामना किया, जिसके बाद यह और ज्यादा मजबूत होकर उभरा। वर्तमान परिस्थितियां उनकी तुलना में कुछ नहीं हैं। आज कई देशों में भुखमरी की नौबत आ गई है। वहां रोटी की कीमत आसमान छू रही है। हमारे एक पड़ोसी देश में आटा खरीदने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगती हैं। भारत में अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कोई देश हम पर हमला करने से पहले हजार बार सोचेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई, उसे दुनिया देख चुकी है। आज भारत अंतरराष्ट्रीय दबावों की परवाह नहीं करता। वह अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष का जो असर हमारे देश पर हो रहा है, उसका हमें एकजुट होकर सामना करना चाहिए। विश्वास कीजिए, भारत जीतेगा, हम सब जीतेंगे। भविष्य में, जब पश्चिम एशिया में शांति हो जाए, तब इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम दोबारा पुराने ढर्रे पर न चल पड़ें। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर निर्भरता कम करनी है।

ट्वीटर टॉक

ओस्लो में मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई। हाल के सालों में भारत-डेनमार्क की दोस्ती में काफ़ी तरक्की हुई है। आने वाले सालों में फिनटेक, इंडस्ट्रीज़, डिफ़ेंस, इनोवेशन और भी बहुत कुछ में इसी तरह का तालमेल देखने को मिल सकता है।

-नरेन्द्र मोदी

पिछले तीन महीने से केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि देश में महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, लेकिन पूरी इगझ सिर्फ़ चुनावों में लगी हुई थी और उन्हें नागरिकों की कोई चिंता नहीं थी। प्रधानमंत्री खुद भ्रम फैला रहे थे कि सब ठीक है।

-अशोक गहलोत

आंखों पर पट्टी बांधकर, रूबिक क्यूब को अपनी धुन पर नचाते हुएवाह, ओह वाह, अफ्फान कुट्टी जी, आप सच में चैंपियन हैं। इसीलिए आपका नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स में दर्ज है। मेरी नज़र में, आपका हुनर एक अनोखी कला है, जो दूसरों को भी आपकी तरह कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है।

-गजेन्द्रसिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

नेकी की राह

है दराबाद के निजाम महबूब अली खां अपने धर्म-गुरु बाबा शर्फूद्दीन की दरगाह 'पहाड़-ए-शरीफ' पर नियम से सालाना उर्स मनाते थे। मजार के पास ही एक अदना से मकान में वह रहते थे और दो दिन तक हिन्दू-मुसलमान सबको खाना खिलाते थे। हिन्दुओं के लिए अलग इंतजाम होता था। उनका हुक्म था कि कोई भी कितना ही खाना खाये वहीं पर खायेगा, पर साथ बांधकर नहीं ले जा सकेगा। दूसरे दिन उनके नौकरों ने एक हिन्दू लड़के को पकड़ लिया, जो छुपाकर खाना लिये जा रहा था। शोरगुल सुनकर निजाम साहब स्वयं वहां आए और लड़के से पूछने लगे उसने खाना क्यूं छुपाया? लड़का निजाम के पांवों में गिरकर रोने लगा और बोला, 'मेरी बहन का पांव भारी है और वह यहां से पांच मील दूर रहती है। उसने मुझे कहा था कि मैं इतनी दूर चल नहीं पाऊंगी, इसलिए तू मेरे लिए रोटियां ले आना।' यह सुनकर महबूब अली पाशा ने अपना एक आदमी लड़के के साथ गाड़ी पर भिजवाया ताकि झूठ-सच का पता चल सके। बात सच निकली। महबूब अली पाशा ने फौरन हुक्म दिया कि, 'लड़की के लिए चांदी के बर्तनों में खाना भेजा जाए और बर्तन वापस नहीं मंगवाये जाएं।'

सामयिक

भोजशाला: इतिहास के आइने में सत्य की खोज

डॉ रामेश्वर मिश्र

मो.: 8318845900

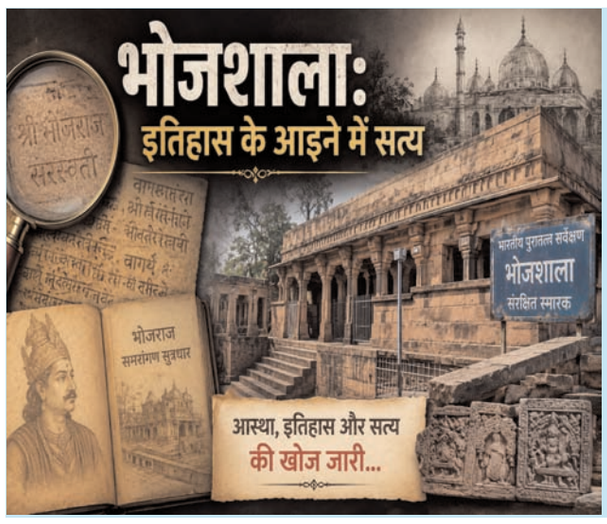

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। इसलिए न्यायालय का दायित्व केवल कानून की व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी होता है। भोजशाला मामले में भी न्यायपालिका ने इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है कि यहाँ संवेदनशील मुद्दों का समाधान भी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से खोजा जाता है।

भोजशाला भारतीय इतिहास, संस्कृति और आस्था का ऐसा अध्याय है, जिससे समय-समय पर समाज, राजनीति और न्याय व्यवस्था को गहन विमर्श के लिए प्रेरित किया है। मध्य प्रदेश के धार नगर में स्थित यह ऐतिहासिक स्थल केवल पत्थरों और स्थापत्य का समूह नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की स्मृतियों, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक संघर्षों का जीवंत प्रतीक है। हाल ही में भोजशाला को लेकर आया न्यायालयीय निर्णय एक बार फिर इस विषय को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आया है। यह फैसला केवल किसी धार्मिक विवाद का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास, पुरातत्व, संवैधानिक प्रक्रिया और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी है।

भोजशाला का नाम आते ही भारतीय इतिहास के महान शासक राजा भोज का स्मरण होता है। परमार वंश के इस प्रतापी राजा ने 11वीं शताब्दी में धार को शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया था। राजा भोज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, साहित्यकार और स्थापत्य प्रेमी भी थे। उनके शासनकाल में संस्कृत साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। धार नगरी को उस समय विद्या की राजधानी माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार भोजशाला संस्कृत अध्ययन और देवी सरस्वती की उपासना का प्रमुख केंद्र थी। यह स्थान विद्वानों, कवियों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का तीर्थ माना जाता था।

भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, कला और विद्या की देवी माना गया है। भोजशाला से जुड़ी अनेक मान्यताएँ इसे माँ वाग्देवी के मंदिर के रूप में प्रस्तुत करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ विद्वानों की सभाएं आयोजित होती थीं, शास्त्रार्थ होते थे और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि हम भारतीय सभ्यता की मूल आत्मा को देखें, तो ज्ञान और शिक्षा को सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की परंपरा में भोजशाला को भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाता है।

मध्यकालीन भारत में सत्ता परिवर्तन और आक्रमणों के साथ अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की संरचनाओं में परिवर्तन हुए। भोजशाला भी इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से अछूती नहीं रही। बाद के काल में यहाँ कमाल मौला मस्जिद का निर्माण हुआ और यह स्थल दो धार्मिक परंपराओं के साझा इतिहास का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि समय के साथ भोजशाला विवाद का विषय बनती चली गई। हिंदू समाज इसे माँ सरस्वती और राजा भोज की धरोहर मानता रहा, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद के रूप में देखता है। यह विवाद केवल धार्मिक पहचान का प्रश्न नहीं, बल्कि ऐतिहासिक व्याख्या और सांस्कृतिक स्मृति का भी विषय है।

हाल ही में आए फैसले ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा ऐतिहासिक प्रमाणों को गंभीरता से देखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी ऐतिहासिक विवाद का समाधान भावनाओं या राजनीतिक नारों के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। यह दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को भी दर्शाता है। न्यायालय ने यह संदेश दिया कि इतिहास की व्याख्या केवल जनभावनाओं से नहीं की जा सकती; इसके लिए निष्पक्ष शोध, पुरातात्विक अध्ययन और प्रमाणिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। भोजशाला विवाद हमें भारतीय इतिहास लेखन की जटिलताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। भारत का इतिहास अनेक परतों से निर्मित हुआ है। यहाँ वैदिक संस्कृति, बौद्ध परंपरा, जैन धर्म, इस्लामी प्रभाव और औपनिवेशिक शासनसभी ने अपनी छाप छोड़ी है। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक स्थल की पहचान केवल एक आयाम में नहीं देखी जा सकती। भोजशाला का प्रश्न भी इसी बहुआयामी इतिहास का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता सह अस्तित्व और समन्वय रही है। यहाँ विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ सदियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। यदि इतिहास को केवल संघर्ष और टकराव के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो समाज में विभाजन बढ़ेगा। किंतु यदि इतिहास को संवाद, समन्वय और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से देखा जाए, तो वह समाज को जोड़ने का कार्य करेगा। भोजशाला के संदर्भ में भी यही अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसे विवाद के बजाय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि भोजशाला को राजनीतिक लाभ और साम्प्रदायिक तनाव का माध्यम बनाने के बजाय शोध और संरक्षण का विषय बनाया जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इतिहासकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को मिलकर इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व पर गहन अध्ययन करना चाहिए। यहाँ उपलब्ध स्थापत्य कला, शिलालेख, मूर्तिकला और अन्य पुरावशेष भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। यदि इनका व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, तो भारतीय मध्यकालीन इतिहास की अनेक अनसुलझी पहेलियों का समाधान संभव हो सकता है।

भोजशाला केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की नक्काशी, स्तंभों की शैली और स्थापत्य संरचना भारतीय कला की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। स्थापत्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थल में परमारकालीन कला के अनेक महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं। यह भारतीय कला इतिहास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इतिहास को किस दृष्टि से देखता है। यदि इतिहास को प्रतिशोध का माध्यम बनाया जाएगा, तो वह संघर्ष को जन्म देगा। किंतु यदि इतिहास को सीख और आत्मबोध का माध्यम माना जाएगा, तो वह समाज को नई दिशा देगा। भोजशाला का प्रश्न हमें यही शिक्षा देता है कि अतीत को समझने के लिए धैर्य, संवेदनशीलता और शोध की आवश्यकता होती है। आज भारत विश्व मंच पर अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में भोजशाला जैसे ऐतिहासिक स्थलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह स्थल भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन सकता है। यदि इसे उचित संरक्षण और वैश्विक पहचान मिले, तो यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। इसलिए न्यायालय का दायित्व केवल कानून की व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी होता है। भोजशाला मामले में भी न्यायपालिका ने इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है कि यहाँ संवेदनशील मुद्दों का समाधान भी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से खोजा जाता है। भोजशाला पर आया फैसला समाज के लिए आत्मचिंतन का अवसर भी है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम इतिहास को केवल विवाद और टकराव के रूप में देखना चाहते हैं, या उसे सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का आधार बनाना चाहते हैं। भारत की आत्मा उसकी विविधता और सहिष्णुता में निहित है। यदि हम इन मूल्यों को बनाए रखेंगे, तभी इतिहास का सही अर्थ समझ पाएँगे।

अंततः भोजशाला का प्रश्न केवल एक इमारत या धार्मिक स्थल का प्रश्न नहीं है। यह भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति, न्याय व्यवस्था और सामाजिक परिपक्वता की परीक्षा है। इतिहास के आइने में सत्य की खोज तभी संभव है, जब समाज भावनाओं के साथ-साथ तथ्यों और विवेक को भी महत्व दे। भोजशाला पर आया फैसला हमें यही संदेश देता है कि सत्य की खोज संघर्ष से नहीं, बल्कि संवाद, शोध और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से होती है। आज आवश्यकता है कि भोजशाला को भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के गौरवशाली प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए। यदि समाज, सरकार और इतिहासकार मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, तो भोजशाला आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल एक विवादित स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की महान विरासत के रूप में जानी जाएगी।

नजरिया

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में सेल्फी का दुरुपयोग भी संभव

महेन्द्र तिवारी

आधुनिक युग में विभिन्न सामाजिक मंचों पर अपने जीवन के विशेष क्षणों को साझा करना मानवीय व्यवहार का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। जब कोई व्यक्ति किसी मनोरम स्थान की यात्रा पर जाता है, मित्रों के साथ आनंदमय समय बिताता है, या प्रतिदिन अपनी नई तस्वीरें अपलोड करता है, तो उसका उद्देश्य अपनी खुशियों और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करना होता है। इन चित्रों के माध्यम से लोग अपनी भावनाएं, जीवनशैली और व्यक्तिगत उपलब्धियां समाज तक पहुंचाते हैं। परंतु, तकनीक की तीव्र गति ने अब इन चित्रों को केवल सुंदर स्मृतियों तक सीमित नहीं रखा है। आज यही तस्वीरें हमारी व्यक्तिगत पहचान और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निरंतर बढ़ते प्रभाव ने अंतरजाल आधारित अपराधों को एक सर्वथा नया और चिंताजनक मोड़ दे दिया है।

वर्तमान समय में सुरक्षा विशेषज्ञ यह चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे दूरभाष या चित्र-यंत्र से ली गई एक सामान्य सी तस्वीर से भी किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान चोरी किए जा सकते हैं और भविष्य में उनका अवांछित दुरुपयोग पूरी तरह संभव है। वर्तमान समय में अत्याधुनिक साधन किसी भी धुंधली तस्वीर को अत्यधिक स्पष्ट और सघन बनाने में सक्षम हैं। तस्वीरों की बारीक रेखाओं को साफ करना, उनके विस्तार को बढ़ाना और उनमें छिपे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपों को पहचानना अब इन प्रणालियों के लिए बहुत सरल हो चुका है। यही कारण है कि मानवीय उंगलियों के पोरों पर पाई जाने वाली अद्वितीय और अत्यंत बारीक रेखाएं भी अब इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण के माध्यम से आसानी से निकाली जा सकती हैं। अंतरजाल सुरक्षा विशेषज्ञ ली चांग ने अपने हालिया प्रदर्शनों में यह प्रमाणित करके दिखाया है कि उच्च गुणवत्ता वाली साधारण तस्वीरों से भी पूरी तरह उपयोग में लाए जा सकने वाले उंगलियों के निशान प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सुरक्षा संकट से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययनों और आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो यह स्थिति और भी भयावह प्रतीत होती है। सुरक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार, यदि कोई तस्वीर लगभग 1.5 मीटर की दूरी से ली गई हो और उपकरण के चित्र-यंत्र की गुणवत्ता उत्तम स्तर की हो, तो उस चित्र से उंगलियों के निशान शत-प्रतिशत स्पष्टता के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि तस्वीर 1.5 से 3 मीटर की दूरी से भी ली गई हो, तब भी आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों की सहायता से उंगलियों के लगभग 50 प्रतिशत तक के रेखा-स्वरूप को सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। यद्यपि सामान्य जन के लिए यह एक साधारण सा आंकड़ा लग सकता है, परंतु अंतरजाल अपराध और पहचान की चोरी करने वाले अपराधियों के लिए इतनी आंशिक जानकारी भी अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। आज के समय में प्रयुक्त होने वाले कई अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण उंगलियों के केवल आंशिक या आधे निशानों के मिलान से भी पहचान सत्यापित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे अपराधियों का काम और अधिक सुगम हो जाता है।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक संवेदनशील और खतरनाक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग कैमरे के सम्मुख अपनी उंगलियों को सीधा करके विजय सूचक या शांति सूचक चिह्न बनाते हैं। युवाओं और बच्चों के बीच यह मुद्रा अत्यधिक लोकप्रिय है और सामाजिक माध्यमों पर ऐसी करोड़ों तस्वीरें उपलब्ध हैं। इस विशिष्ट मुद्रा में व्यक्ति की उंगलियों के पोर सीधे उपकरण के सामने केंद्रित होते हैं, जिसके कारण तस्वीर में उंगलियों की रेखाएं सबसे अधिक स्पष्ट और प्रकाशमान दिखाई देती हैं। जापान के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कई वर्ष पूर्व ही इस विषय पर गहन शोध करके दुनिया को सचेत किया था कि इस प्रकार की मुद्राओं वाली तस्वीरों से उंगलियों के निशानों को बहुत सुगमता से पढ़ा जा सकता है। अब जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है, तब इस तकनीकी खतरे की गंभीरता पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है।

उंगलियों के निशानों के लीक होने का यह संकट किसी भी सामान्य कूटशब्द की चोरी से अत्यधिक गंभीर माना जाता है। यदि किसी उपयोगकर्ता का कोई कूटशब्द या गोपनीय संख्या चोरी हो जाती है, तो वह तत्काल उसे बदलकर एक नया और सुदृढ़ कूटशब्द निर्मित कर सकता है। इसके विपरीत, मनुष्य की उंगलियों के निशान उसके संपूर्ण जीवनकाल में अपरिवर्तनीय रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी उंगलियों के प्राकृतिक निशानों को बदल नहीं सकता है। यही मुख्य कारण है कि इस प्रकार के जैव-पहचान संबंधी आंकड़ों का दुरुपयोग किसी भी व्यक्ति के लिए दीर्घकालिक समस्या उत्पन्न कर सकता है। एक बार यदि किसी अपराधी समूह या अवांछित प्रणाली के पास किसी नागरिक की उंगलियों के निशानों का सटीक रेखा-स्वरूप पहुंच जाता है, तो वह अपराधी भविष्य में कई वर्षों तक उस व्यक्ति के नाम पर विभिन्न प्रकार के वित्तीय अपराध करने का प्रयास कर सकता है। आज संपूर्ण विश्व में आधुनिक दूरभाष, संगणक, बैंकिंग सेवाएं, सरकारी प्रणालियां और उच्च सुरक्षा वाले संस्थान उंगलियों के निशानों पर आधारित पहचान प्रणाली पर पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं। अधिकांश कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए इन जैव-पहचान उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हवाई अड्डों, सीमा सुरक्षा चौकियों और अन्य संवेदनशील राष्ट्रीय संस्थानों में भी पहचान की पुष्टि के लिए उंगलियों के निशानों का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। ऐसी संवेदनशील व्यवस्था में यदि किसी निर्दोष नागरिक की जैव-पहचान संबंधी गोपनीय जानकारी गलत हाथों में चली जाती है, तो उसके परिणामस्वरूप पहचान की चोरी, गंभीर बैंकिंग धोखाधड़ी, बैंक खातों से धन की अवैध निकासी और प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश जैसी अत्यंत विकट समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित इस तकनीक के क्षेत्र में हो रहे नित नए शोधों से कुछ और चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि मशीन पर आधारित आधुनिक कलन विधियां अब ऐसे कृत्रिम अथवा नकली उंगलियों के निशान भी तैयार कर सकती हैं जो विभिन्न सुरक्षा उपकरणों को भ्रमित करने में सक्षम हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में ऐसे कृत्रिम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित निशानों को विकसित करने में सफलता पाई है जिन्हें कुछ संवेदनशील सुरक्षा प्रणालियों ने वास्तविक मानकर स्वीकार कर लिया। यह उभरती हुई स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले समय में अंतरजाल सुरक्षा की चुनौतियां मानवीय कल्पना से भी अधिक जटिल और बहुआयामी होने वाली हैं।

हालांकि, इस विषय के दूसरे पहलू को स्पष्ट करते हुए विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सामाजिक माध्यमों पर डाली गई प्रत्येक तस्वीर से तत्काल कोई बैंक खाता अवरुद्ध नहीं हो जाता और न ही हर सामान्य चित्र इतना बड़ा संकट उत्पन्न करता है। किसी भी तस्वीर से उंगलियों के निशानों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए अत्यधिक अनुकूल और सटीक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए चित्र लेते समय प्रकाश की व्यवस्था अत्यंत उत्तम होनी चाहिए, उपकरण का केंद्रन पूरी तरह से उंगलियों पर होना चाहिए और तस्वीर की स्पष्टता बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान समय के अधिकांश अत्याधुनिक उपकरण केवल उंगलियों के निशानों पर ही पूरी तरह आश्रित नहीं होते हैं। उनमें सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जैसे गुप्त संख्या, चेहरे की पहचान और डेटा सुरक्षा प्रणालियां भी अंतर्निहित होती हैं। इसके बावजूद, तकनीक के इस निरंतर होते विकास के कारण इस खतरे को कदापि कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस नए युग के अंतरजाल खतरों से निपटने के लिए सामाजिक माध्यमों का उपयोग करने वाले नागरिकों के बीच व्यापक जागरूकता का होना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। आज के दौर में अंतरजाल और सामाजिक मंचों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, परंतु अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करके इस खतरे को न्यूनतम अवश्य किया जा सकता है। तस्वीरें लेते समय उपकरण की ओर सीधे उंगलियां दिखाने वाली मुद्राओं से पूर्णतः बचना चाहिए। अत्यधिक निकटता से ली गई उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सार्वजनिक मंचों पर साझा करने से परहेज करना चाहिए। यदि ऐसी तस्वीरें अपलोड करना आवश्यक ही हो, तो अपलोड करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता को थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि यदि कोई उन्हें अत्यधिक बड़ा करके भी देखे, तो उंगलियों की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई न दें। इसके साथ ही, अपने व्यक्तिगत खातों की गोपनीयता सेटिंग्स को सदैव मजबूत रखना चाहिए ताकि अपरिचित व्यक्ति आपकी तस्वीरों तक न पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त, केवल उंगलियों के निशानों पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था पर ही पूर्ण निर्भरता उचित नहीं है। सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और व्यक्तिगत खातों में दोहरी प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत गुप्त संख्या, संदेश आधारित तत्काल सत्यापन और अन्य सुरक्षात्मक उपायों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। अंतरजाल अपराधी सदैव हमारी असावधानी और सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों की ताक में रहते हैं, इसलिए इस आभासी संसार में निरंतर सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा कवच है। अंततः, यह तकनीक का युग है जो मानव जीवन को सुगम बनाने के साथ-साथ नई चुनौतियां भी दे रहा है। आज एक साधारण सा स्व-चित्र केवल एक सुंदर दृश्य नहीं है, बल्कि वह हमारी अत्यंत निजी जानकारी का स्रोत भी बन सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक के लाभों का सहर्ष उपयोग करें, किंतु उसके छिपे हुए खतरों के प्रति भी समान रूप से सजग रहें। थोड़ी सी सतर्कता हमें भविष्य के किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. **Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

झारखंड में लगातार सातवें वर्ष गंगा की मुख्य धारा में प्रदूषण नहीं: नमामि गंगे

नई दिल्ली/भाषा। गंगा की मुख्य धारा का सबसे छोटा हिस्सा झारखंड से होकर गुजरता है और यह हिस्सा लगातार सात वर्षों से प्रदूषण-मुक्त नदी खंड (पीआरएस) का रिकॉर्ड बनाए हुए है। यह जानकारी 'नमामि गंगे' से संबंधित रिपोर्ट से मिली है। गंगा बेसिन के पांच राज्यों में झारखंड शामिल है।

केंद्र के इस प्रमुख नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत झारखंड के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए 'नमामि गंगे' ने कहा कि इस राज्य का मॉडल इसलिए अलग है, क्योंकि इसमें दूषित नदी के किसी हिस्से के पुनरुद्धार के बजाय प्रदूषण रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।'नमामि गंगे' ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''जहां अधिकतर नमामि गंगे अभियान की कहानियां सफाई से जुड़ी होती हैं, वहीं झारखंड में नदी को गंदा होने से रोका जाता है।''इसने कहा, ''वर्ष 2018 में, सीपीसीबी को झारखंड से गुजरने वाली गंगा की मुख्यधारा प्रदूषण-मुक्त मिली थी और नमामि गंगा अभियान के सात साल बाद 2025 में भी, इसमें प्रदूषण नहीं मिला।

'तुम वाकई बहुत हॉट हो', कॉकटेल-2 में कृति सेनन के लुक पर रश्मिका मंदाना ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया

मुंबई/एजेन्सी

मनोरंजन जगत में अक्सर अभिनेत्रियों के बीच कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, लेकिन अभिनेत्री कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। दोनों जल्द ही अभिनेता शाहिद कपूर के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आएंगी। हाल ही में 'कॉकटेल 2' के एक गाने के लॉन्च इवेंट के दौरान, रविवार रात मुंबई के एक मशहूर फाइव-स्टार होटल में रश्मिका मंदाना ने अपनी को-स्टार कृति सेनन की जमकर तारीफ की। वहीं, कृति ने भी रश्मिका को बेहद मिलनसार और सच्ची इंसान बताया। दरअसल, 'कॉकटेल 2' में कृति सेनन का लुक उनके करियर के सबसे हॉट और ट्रेंडी लुक्स में से एक बताया जा रहा है। इसमें उन्होंने स्टाइलिश बीचवियर, श्रग्स और गर्मियों की स्टाइलिश ड्रेस पहनी हैं, जो उन्हें मॉडर्न और फ्रेश लुक दे रही हैं। अभिनेत्री के इस लुक की हर तरफ तारीफ हो रही है। इसी दौरान रश्मिका मंदाना भी खुद को कृति की तारीफ करने से रोक नहीं पाईं।

कार्यक्रम के दौरान रश्मिका मंदाना ने कहा कि फिल्म में कृति का लुक बेहद आकर्षक है। इसी बीच, कृति की तारीफ करते हुए रश्मिका उत्साह में कुछ ऐसा भी बोल गईं कि वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े।

रश्मिका मंदाना ने कहा, हम जानते हैं कि शाहिद और कृति के बीच कैसी केमिस्ट्री है, लेकिन 'कॉकटेल 2' में कुछ ऐसा है, जो बहुत अलग और जादुई है। जब हमने 'माशूका' की झलकियां देखीं, तो उसकी एक झलक मिली। मुझे पता है कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि मैंने फिल्म के जिन भी सीन के बारे में सुना है, वे सभी शानदार हैं।मीडिया के सामने फिल्म और उसमें दिखने वाली केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए रश्मिका ने कहा, लेकिन 'कॉकटेल 2' में कुछ बहुत अलग है। तुम बहुत हॉट लग रही हो, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है... और तुम सच में बहुत ज्यादा हॉट हो। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग फिर हंसने लगे। रश्मिका ने आगे कहा, कृति कमाल की लग रही हैं, मुझे माफ करना। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

संबोधन

रायबरेली में 'महिला संवाद' कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर बोला हमला।

भारत में एक्टर्स को अपने ही लोग बुरी तरह ट्रोल करते हैं, यह शर्मनाक है : अमीषा पटेल

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री अमीषा पटेल एक्टिंग के साथ ही कई मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखती नजर आती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के ट्रोलिंग कल्चर पर तीखा हमला बोला। अमीषा का कहना है कि भारत में एक्टर्स को अपने ही लोग हॉलीवुड सितारों से ज्यादा बुरी तरह ट्रोल करते हैं, जो बेहद दुखद और शर्मनाक है। अमीषा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय मानसिकता अब दूसरों को नीचे गिराने वाली हो गई है। अमीषा ने बड़े इवेंट्स में सितारों के लुक और पहनावे को लेकर फैल रही नकारात्मकता पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे दुखद और शर्मनाक बताया। अमीषा ने लिखा, भारत में एक्टर्स को अपने ही लोग, हॉलीवुड सितारों की तुलना में उनके अपने देश में ज्यादा बुरी तरह ट्रोल करते हैं, जो बहुत दुख की बात है। हालांकि, ये कोई पहली बार नहीं है, जब अमीषा पटेल खुलकर अपनी बात रखती नजर आईं। इससे पहले वह एक्टर्स के पीआर गेम को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में अपने एक्स पोस्ट पर कहा कि वे अपने बयान पर पूरी तरह कायम हैं। दरअसल, मुंबई में पैपराजी से बात करते हुए अमीषा ने कहा था, सही तो कहा मैंने। आजकल सभी अपने आप को नंबर वन समझते हैं। अमीषा ने एक्स पोस्ट पर यंग एक्टर्स पर तंज कसते हुए लिखा था कि जिन्होंने अभी तक कोई 200 करोड़ क्लब की फिल्म नहीं दी है, वे पीआर टीम को पैसे देकर खुद को नंबर 1 और नंबर 2 बता रही हैं। अमीषा ने साफ कहा, खुद को सुपरस्टार तभी कहो, जब तुमने कोई ऐसा काम किया हो जो इतिहास रच दे। पीआर के खेल खेलना बंद करो। यह कड़वी सच्चाई है।

रूस के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं पुतिन

बीजिंग/एपी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा समाप्त होने के एक सप्ताह से भी कम समय के भीतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीनी नेता शी चिनफिंग से मिलने के लिए चीन आ रहे हैं। पुतिन मंगलवार और बुधवार को चीन में रहेंगे। चीन एक ओर अमेरिका के साथ स्थिर संबंध बनाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह रूस के साथ मजबूत संबंध भी बरकरार रखना चाहता है। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन और शी की योजना दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के साथ-साथ ''प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों'' पर भी चर्चा करने की है। यह यात्रा 2001 में हस्ताक्षरित चीन-रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है।

वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और रूसी तेल एवं गैस का सबसे बड़ा ग्राहक भी है। रूस को उम्मीद है कि ईरान में युद्ध से मांग और बढ़ेगी। चीन ने तटस्थ रुख अपनाते हुए अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे हैं। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंगलवार को बताया कि पुतिन ने अपनी यात्रा से पहले जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि द्विपक्षीय संबंध ''वास्तव में अभूतपूर्व स्तर'' पर हैं और यह रिश्ता वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने सोमवार को कहा था कि ट्रंप और पुतिन की यात्राओं के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि रूसी नेता की यह यात्रा पुतिन और शी चिनफिंग के बीच चार फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बातचीत के बाद तय की गई थी। बीजिंग स्थित थिंक टैंक 'सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन' के उप महासचिव वांग ज़िचेन ने कहा, ''ट्रंप की यात्रा का उद्देश्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना था, वहीं पुतिन की यात्रा एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार को आश्वस्त करने के बारे में है। चीन के लिए, ये दोनों रास्ते एक दूसरे से अलग नहीं हैं।'' पुतिन ने पिछली बार सितंबर 2025 में चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के सम्मान में आयोजित सैन्य परेड देखी और शी जिनपिंग के साथ वार्ता की।

ट्रेलर लॉन्च

मुंबई में फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च पर अभिनेता राम चरण और जाह्नवी कपूर ने बिखेरा जलवा।

पूजा भट्ट ने विंटेज लुक शेयर कर जाहिर की अपनी अनोखी ख्वाहिश

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री पूजा भट्ट अपनी बोल्ड और रियलिस्टिक भूमिकाओं से एक मजबूत और अलग पहचान के लिए जानी जाती हैं। सोमवार को उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में पूजा भट्ट का लुक बेहद आकर्षक और विंटेज नजर आ रहा है। उनकी आंखों की गहराई और चेहरे का अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। अभिनेत्री ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ओह! काश मैं गैटसबी की दुनिया में रहने वाली एक फ्लैपर गर्ल होती। बता दें कि 'द ग्रेट गैटसबी' अमेरिकी लेखक एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। 1925 में प्रकाशित, यह उपन्यास 1920 के दशक के 'जैज युग' और 'अमेरिकी सपने' की सच्चाई और उसके खोखलेपन को उजागर करता है। इस कालजयी कहानी की लोकप्रियता को देखते हुए इस पर कई नाटक और फिल्में बन चुकी हैं। इसमें वर्ष 2013 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रेट गैटसबी' (लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत) काफी लोकप्रिय है।

इसकी कहानी कथावाचक निक कैरवे हैं, जो न्यूयॉर्क के पास लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट एग में रहने आते हैं। उनके पड़ोसी जे गैटसबी हैंजो एक बेहद अमीर और रहस्यमयी करोड़पति हैं। गैटसबी अपने आलीशान बंगले में हर हफ्ते भव्य पार्टियां देते हैं। इन पार्टियों का मुख्य उद्देश्य उनकी पूर्व प्रेमिका डेजी बुकानन को आकर्षित करना होता है। डेजी अब शादीशुदा हैं और गैटसबी अपने अतीत के प्यार को फिर से पाना चाहते हैं। 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री पूजा भट्ट ने मात्र 17 साल की उम्र में अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म 'डैडी' (1989) से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री' का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद पूजा ने 'दिल है कि मानता नहीं' (1991), 'सड़क' (1991), 'सर' (1993) और 'जख्म' (1998) जैसी फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की। अभिनय के अलावा, उन्होंने 'पाप' (2003) और 'जिस्म 2' (2012) जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है।

शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया : मेनका गांधी

नई दिल्ली/भाषा

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने मंगलवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने दलील दी कि न्यायालय के पिछले निर्देश देशभर में लागू नहीं हुए और उन्हें पूरा करना तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं था।

मेनका की यह टिप्पणी शीर्ष अदालत द्वारा आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने और उनकी नसबंदी करने से जुड़े अपने नवंबर 2025 के आदेश को वापस लेने से इनकार करने के बाद आई।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार में किसी कुत्ते के हमले के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है।

अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, न्यायालय ने कुछ नहीं किया है, उसने बस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि यदि आप चाहें तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पिछले छह महीनों में आदेश के क्रियान्वयन की व्यापक विफलता पर ध्यान दिए बिना, केवल अपने पिछले निर्देशों को ही दोहराया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''इसने (न्यायालय ने) केवल इतना कहा है कि हमने नवंबर में जो कहा था, उसे किया जाना चाहिए था। नवंबर से लेकर अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। छह महीने बीत चुके हैं। एक भी 'पशु जन्म नियंत्रण' (एबीसी) केंद्र नहीं बनाया गया है।'' उन्होंने आगे कहा, ''एक भी आश्रय स्थल नहीं बनाया गया है। न किसी अस्पताल, न बस पड़ाव, न किसी विद्यालय, न महाविद्यालय, किसी ने भी कुत्तों को नहीं हटाया है, क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते.... यह तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है।''

उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले आदेश को वापस लेने संबंधी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों को काटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और अधिकारी इस ''कठोर जमीनी वास्तविकताओं'' की अनदेखी नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया के पीठ ने पाया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, आश्रय और पशु जन्म नियंत्रण ढांचे का क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ''छिटपुट, कम वित्त-पोषित और असमान'' बना हुआ है।

पीठ ने कहा कि लंबे समय तक निष्क्रियता और संस्थागत प्रतिबद्धता की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया है तथा इसके लिए तत्काल प्रणालीगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

मसाला फिल्मों से कोर्टरूम ड्रामा तक, सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कैसे बदला उनका फिल्मी सफर

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह की फिल्में की हैं। इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म 'सिस्टम' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने आईएएनएस से अपने फिल्मी सफर, पुराने किरदारों और बदलती पसंद के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि समय के साथ न सिर्फ उनके काम करने का तरीका बदला, बल्कि अब वह अपने रोल्स को पहले से ज्यादा सोच-समझकर चुनती हैं। आईएएनएस से बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने अपने शुरुआती दौर की फिल्मों को याद किया। उन्होंने कहा, जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा थी जो कलरफुल, मनोरंजन से भरपूर और पूरी तरह मसाला अंदाज की होती थीं। 'आर. राजकुमार' और 'राउडी राठौर' जैसी फिल्मों में काम करके काफी मजा आया। उस समय मैं अपने करियर के ऐसे दौर में थी, जहां

दर्शक मुझे उसी अंदाज में देखना पसंद करते थे।'' उन्होंने कहा, ''मैंने इन किरदारों को पूरी ईमानदारी और खुशी के साथ निभाया। लेकिन हर कलाकार के जीवन में अलग-अलग चरण आते हैं और हर दौर में दर्शकों की पसंद और इंडस्ट्री की मांग भी बदलती रहती है।''

अभिनेत्री ने आगे कहा, ''अब मैं अपने करियर के ऐसे मोड़ पर हूं, जहां मैं सिर्फ वही काम करना चाहती हूं, जो मुझे अंदर से संतुष्टि देता हो। अब मैं खुद को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में देखती हूं, जो हर तरह के किरदार निभा सके। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे ऐसी कलाकार के रूप में देखें, जिसे किसी भी तरह की फिल्म में रखा जा सके। अब मैं सिर्फ वही काम कर रही हूं, जो मैं सच में करना चाहती हूं।''

सोनाक्षी ने अपने पुराने फिल्मी सफर को लेकर भी आभार जताया। उन्होंने कहा, अगर मैंने शुरुआत में मसालेदार फिल्में नहीं की होतीं, तो शायद आज मुझे ऐसे अलग और गंभीर किरदार निभाने का मौका नहीं मिलता। मुझे फिल्मों ने दर्शकों का प्यार, पहचान और समर्थन दिलाया। लोगों के प्यार की वजह से ही आज मैं अपने मन के किरदार को चुन पा रही हूं और नई तरह की कहानियों का हिस्सा बन रही हूं।''अपनी आने वाली फिल्म 'सिस्टम' के बारे में बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए काफी खास है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें वह पहली बार वकील की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में अभिनेत्री एक स्टेनोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी। 'सिस्टम' फिल्म 22 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

मौत

झाड़ग्राम में आम के बाग में मृत मिले हाथी की वन विभाग ने शुरू की जांच, करंट लगने से मौत की आशंका।

'मनगढ़ंत खबरें बंद करें'...: मौनी रॉय

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री मौनी रॉय और सूरज नांबियार के अलग होने की खबरों को लेकर चल रही अफवाहों और अटकलों पर सूरज नांबियार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सोमवार को सोशल मीडिया पर अपना जारी करते हुए मीडिया से न केवल मनगढ़ंत खबरें को बंद करने बल्कि दोनों को आगे का रास्ता शांति से तय करने की अपील भी की। सूरज ने सारी अटकलों को सिरे से खारिज कर हुए इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर लिखा, हमारी रिपोर्ट्स गलत तरीके से और पूरी तरह से गलत इरादे से बनाई गई हैं। मैं एक बार और हमेशा के लिए रिकॉर्ड साफ कर दूं। कोई एलिमनी नहीं है। कोई झगड़ा नहीं है। इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मौनी और मैंने एक-दूसरे की इज्जत करते हुए और एक-दूसरे की भलाई का पूरा ध्यान रखते हुए, एक साथ अलग होने का फैसला किया। यही सच है। बाकी जो कुछ भी बताया जा रहा है वह मनगढ़ंत है। कुछ लोग जानबूझकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज ने स्पष्ट रूप से कहा कि मौनी और उनके बारे में या किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, दूसरे लोगों को इसमें घसीटना ठीक नहीं है, खासकर उन दोस्तों को जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।

सूरज ने मीडिया ऑर्गनाइजेशंस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, मीडिया हाउस ने ऐसी बातें गढ़ी हैं, जो असल में हैं ही नहीं। ये रिपोर्ट्स बिना किसी वेरिफिकेशन के प्रकाशित की गई हैं, जो बहुत गलत है। जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने के सामने चुप रहना मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने अपने संयुक्त बयान का जिक्र करते हुए कहा, हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में वह सब कुछ कहा गया था जो कहना जरूरी था। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि उसका सम्मान करें और हमें शांति से अपनी जिंदगी आगे बढ़ने दें। दरअसल, कुछ दिन पहले ही मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद उनके अलग होने की खबरें तेजी से वायरल हो गईं। इसके बाद दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर अलग होने की पुष्टि की थी। हालांकि, खबर ये भी है कि दोनों फिर से एक-दूजे को फॉलो करने लगे हैं।

माहेश्वरी महिलाओं ने गांव में बांटी सोलर लाइट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। माहेश्वरी महिला मंडल ने अपनी स्थापना के गोल्डन जुबली वर्ष के शुभारंभ पर सोमवार को कड़ाही मेडुतिरुवल्लूर जिला में 51 सोलर लाइट भेंट की। सूरज बाहेती परिवार के सौजन्य से सोलर लाइट प्रोजेक्ट की शुरूआत की। सूरज बाहेती ने सभी सदस्याओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में शामिल बच्चों को कोषाध्यक्ष शोभना सिकची द्वारा जूस पैकेट्स, सहसचिव पायल गोयदानी द्वारा बिस्कुट पैकेट्स और चॉकलेट तथा सूरज बाहेती ने चप्पलें भेंट की। ग्रीष्मा राठी ने सभी को धन्यवाद दिया। अंत में सभी सदस्याओं ने अति प्राचीन शिवमंदिर के दर्शन किए।

डागा बने माहेश्वरी क्लब के अध्यक्ष जेठा बने सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय साहुकारपेट स्थित माहेश्वरी भवन में रविवार को माहेश्वरी क्लब चेन्नई की 49वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। इस अवसर पर सर्वसम्मति से मुकुल डागा को अध्यक्ष एवं गौरव जेठा को सचिव पद चुना गया। चुनाव अधिकारी ओमप्रकाश बागड़ी एवं संजय मूंदड़ा ने नवीन कार्यकारिणी में चुने गए सदस्यों की घोषणा की। नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर देवकिशन काबरा, महिला उपाध्यक्ष के रूप में संतोष बिसानी, सहसचिव सुरेश कोठारी एवं कोषाध्यक्ष संदीप काबरा को चुना गया।

इसके अलावा ही रश्मि चांडक, अर्चना भट्टड, मनोज साबू, लोकेंद्र मालपानी, अनुराग माहेश्वरी, कृष्णकुमार नथानी, मुकेश चांडक, रमेश सुरजन एवं विकास शारदा को कमेटी सदस्य बनाया गया है। सभा में पूर्व अध्यक्ष सुनील शारदा एवं सचिव मुरलीमनोहर लखोटिया ने गत वर्ष के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकुल डागा ने स्वागत किया। सचिव गौरव जेठा ने धन्यवाद दिया संचालन सीमा सुरजन ने किया। इस अवसर पर गौरीशंकर राठी, अशोक मूंदड़ा, प्रमोद मालपानी, कमल मेहता, सत्यनारायण भूतड़ा, जेठमल शारदा, सुनीता डागा आदि उपस्थित थे।

कराबी निगम कार्यालय में वार्षिक स्वास्थ्य जांच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में निगम की सीमा में आने वाले 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम पर एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक ए.वेणुगोपाल ने किया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी आरओ पीवी रामनाथन केके नगर अस्पताल के डॉ. पुष्पेंद्र गौतम और अयानवरम के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। शामिल हुए। नियोक्ता संघ के प्रतिनिधियों और चेन्नै क्षेत्र के कुछ नियोक्ताओं ने भी बैठक में भाग लिया। सत्र के दौरान पीवी रामनाथन ने नए श्रम कानूनों की व्याप्ति में आने वाले कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में कर्मचारी कल्याण और अनुपालन के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के महत्व पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में एक इंटरैक्टिव प्रश्न सत्र आयोजित किया गया, जिसके दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में नियोक्ताओं की शंकाओं का समाधान किया गया।

नकारात्मक विचार मृत्यु से बढ़कर और सकारात्मक सोच अमृत के समान : कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के अलसूर स्थित जैन स्थानक में विराजित राष्ट्रसंत कमलमुनिजी कमलेश ने अपने दैनिक प्रवचन में कहा कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए समय, शक्ति, और पैसा कितना भी लगा दो, यदि वह नकारात्मक सोच से ग्रसित है तो साक्षात परमात्मा भी उसको सफलता नहीं दिला सकते। विश्व के सभी महापुरुषों और धर्मों ने नकारात्मक सोच को अंधकार और पतन का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच से आत्मबल टूटता है, शरीर रोगों का घर बनता है और कर्मों का संचय होता है। धर्म और उपासना महान है जो नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। नकारात्मक विचार अपने आप में मृत्यु से बढ़कर है। मुनिश्री ने कहा कि नकारात्मक विचार वाला दिशाहीन होकर भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, अनंत जन्मों का नुकसान कर देता है। ऐसे विचार वालों के लिए दुनिया की कोई ताकत उसका भला नहीं कर सकती।

सकारात्मक सोच अनंत ऊर्जा जोश उत्सव और उमंग का संचार करती है। सकारात्मक सोच अमृत से बढ़कर है, सफलता के लिए संजीवनी बूटी होती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, उसे परिणाम की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, निश्चित सफलता उसके चरण चूमेगी।

डूंगरवाल परिवार ने स्वास्तिक सेवा ट्रस्ट को जलसेवा हेतु प्रदान की पानी की ट्रॉली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय स्वस्तिक सेवा ट्रस्ट परिवार की ओर से शहर में जनसेवा व पादुका सेवा जैसे अनेक सेवा कार्य किए जाते हैं। उनके निस्वार्थ सेवाकार्यों को देखते हुए मार्गदर्शक फाउंडेशन के कमलेश डूंगरवाल द्वारा स्वास्तिक सेवा ट्रस्ट को पानी की वाटर ट्रॉली भेंट की।

ट्रस्ट द्वारा पहले ही पानी की दो ट्रॉलियों जलसेवा कर रही हैं। इसी सेवा भावना के सम्मान स्वरूप स्वस्तिक सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन सतीश मित्तल, अध्यक्ष बिमल सरावगी, अशोक गर्ग, अजय खेमका, चंद्र प्रकाश पोद्दार, भागवत अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, गौरव जिंदल सहित अनेक सदस्यों ने डूंगरवाल का सम्मान किया। सतीश मित्तल ने डूंगरवाल परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनके सहयोग का नहीं, बल्कि उनके उदार हृदय, सामाजिक उत्तरदायित्व और जनकल्याण की भावना का सम्मान है।

जीतो 'नेक्स्टजेन टॉक्स' कार्यशाला में 35 प्रतिभागियों को मिला प्रमाणपत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) साउथ लेडीज़ विंग द्वारा सक्षम पहल के अंतर्गत 'नेक्स्टजेन टॉक्स, मास्टर दि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग' नामक 5 दिवसीय कार्यशाला का दीक्षांत समारोह जीतो कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने स्वागत करते हुए कार्यशाला को आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और परिवर्तन की सुंदर यात्रा बताते हुए कहा कि पब्लिक स्पीकिंग केवल मंच पर बोलना नहीं, बल्कि निर्भय होकर स्वयं को अभिव्यक्त करना है। मुख्य अतिथि कोमल भंडारी ने कहा कि इस कार्यशाला में बच्चों ने मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक विषयों पर ज्ञान प्राप्त किया। आज की युवा पीढ़ी ज्ञान और जागरूकता को नई दिशा दे रही है। पायलट फैकल्टी अमित सिंघवी ने कहा कि कार्यशाला के दौरान उन्होंने स्वयं भी बच्चों से बहुत कुछ सीखा और उनकी सोच, संवेदनशीलता तथा क्षमताओं को गहराई से समझने का अवसर मिला। को-फैकल्टी कृषा शाह ने कहा कि बच्चों के साथ हर दिन नई सीख और खुशी से भरा रहा।

उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की आपस में तुलना न करें, क्योंकि इससे उनके आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। संयोजक निशा कोठारी ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करना था। सहसंयोजक निशा तुकालिया ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को दीक्षांत समारोह में माता-पिता एवं फैकल्टी सदस्यों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

शिवकाशी में तेरापंथ महिला मंडल की संगठन यात्रा आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिवकाशी। संगठन यात्रा के अंतर्गत अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल तमिलनाडु एवं केरल प्रभारी तिरपुर की अनीता बरड़िया तथा सेलम की शालिनी लुंकड़ शिवकाशी पहुंची। मंडल अध्यक्षा सुशीला जैन ने सभी का स्वागत किया। वरिष्ठ संरक्षिका संपतदेवी दुगड़, सुशीला जैन, मंत्री कुसुम बैद आदि ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान किया। संगठन यात्रा में शालिनी लुंकड़ ने संगठन के चार मुख्य आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में केवल हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता है। अनीता बरड़िया ने राष्ट्रीय अध्यक्षा के संदेश के माध्यम से उनके विजन को साझा किया तथा महिलाओं को प्रतिदिन अपने लिए 48 मिनट निकालकर स्वयं को सक्षम बनाने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। कुसुम बैद ने धन्यवाद दिया।

सुरक्षा और विकास के लिए मितव्ययता और मर्यादाओं का परिपालन परम आवश्यक : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बल्लारी। जिले के हलेदारोजी ग्राम में सरकारी माध्यमिक विद्यालय में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। उतार-चढ़ाव, सुख-दुःख मनुष्य की जिंदगी की नियति है। सुरक्षा और विकास के लिए जीवन में सात्विकता, मितव्ययता और मर्यादाओं का परिपालन परम आवश्यक है। जब हम मर्यादाओं को लांघते हैं तब समस्याओं का उद्भव होता है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य मर्यादाओं को समझना ही नहीं चाहता, आहिस्ता आहिस्ता वह अनेक सीमाएं लांघता जा रहा है। यही हम सबके दुःखों का मुख्य कारण है। बड़ा बनने की चाह और अभिमान, ईर्ष्या व भेदभावों ने विश्वयुद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है। एक-दूसरे को निगलने या समाप्त करने की होड़ लगी है। शक्ति, संपत्ति और संसाधन तबाह हो रहे हैं। तबाही का मंजर ऐसा है कि विकास की परिभाषा ही बदल गई है। अब कब क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में मानवीय समाज के पास यही विकल्प है कि वह प्रबुद्ध बनें, सावधानी बरतें, अपने विवेक को जगाएं, भविष्य की सुरक्षाओं और संभावनाओं को देखते हुए जीवन जीएं।ङ्कआचार्यश्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां मानवीय समाज के अनुकूल नहीं हैं। यह देखते हुए हर एक व्यक्ति को सोच समझकर, अपव्यय रोककर, सादगी पूर्वक जीवनयापन करने का प्रयत्न करना चाहिए।

'महावीर जैन साधर्मिक सहायता फण्ड' की नई कार्यकारिणी समिति गठित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। उपाध्यायश्री केवलमुनिजी की प्रेरणा से स्थापित महावीर जैन साधर्मिक सहायता फण्ड की साधारण सभा श्रीरामपुरम में सम्पन्न हुई जिसमें संघ की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें बताया गया कि श्रीरामपुरम में 21 ट्रस्टियों से इस फण्ड का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राप्त रकम के ब्याज से हर वर्ष समाज के असहाय, असमर्थ, कमजोर स्थिति वाले साधर्मिकों की यथासंभव सहायता की जाए।संतोषकुमार दक ने आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। आगामी कार्यकाल के लिए मार्गदर्शक गणेशमल गुगलिया ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी की घोषणा की जिसमें अध्यक्ष देवीलाल सुखलेचा, उपाध्यक्ष महावीरकुमार दक, मंत्री बालूराम दलाल एवं कोषाध्यक्ष संतोषकुमार दक के नाम की घोषणा की गई। गणेशमल गुगलिया, तेजराज खिवेंसरा एवं ताराचन्द गुगलिया को मार्गदर्शक बनाया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने संस्था में दान की अच्छी राशि की घोषणा की। बालूराम दलाल ने सभी को धन्यवाद दिया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सम्मान

अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक युवक महासंघ बेंगलूरु के सदस्यों ने वीवी पुरम पुलिस स्टेशन में दावणगेरे से आए नवनियुक्त इंस्पेक्टर शंकर से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर महासंघ के मनोज बाफना, सुशील गोटावत, पदमचंद भुरट सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

हाथी शिविर हादसा: पर्यटक महिला के बाद घायल हाथी 'मार्थंडा' की भी मौत

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित डुबारे हाथी शिविर में दो प्रशिक्षित हाथियों की लड़ाई में घायल हुए हाथी 'मार्थंडा' की मंगलवार को मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले दोनों हाथियों की लड़ाई में एक महिला पर्यटक की भी जान चली गई थी। अधिकारियों ने बताया कि 18 मई को हाथियों को नहलाने के दौरान 'कंजन' और 'मार्थंडा' के बीच भिड़ंत हो गई। लड़ाई में घायल मार्थंडा का इलाज चल रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।घटना के दौरान तमिलनाडु की पर्यटक तुलसी (33) हाथियों को नहलाते देख रही थीं। मार्थंडा के गिरने पर वह उसके नीचे दब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.